भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत अखबार

R.N.I.Regd.No.:RAJHIN/2015/61758

जागरूक जनता

22 जुलाई - 28 जुलाई 2026

jagrukjanta.net

आषाढ़, पक्ष - शुक्ल, तिथि - नवमी , संवत 2083 पृष्ठ : 8 जयपुर बुधवार वर्ष-12, अंक-21, मूल्य ₹ 5/- वार्षिक मूल्य : ₹ 250/- साप्ताहिक

हादसों के बाद संबंधित व्यक्ति को सजा नहीं, बल्कि फर्स्ट एड दिया जाता है!

सटीक

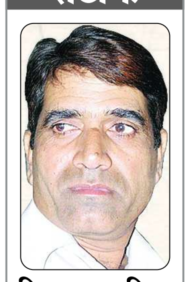

शिव दयाल मिश्रा
@jagrukjanta.net

जीवन की हर सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हर व्यक्ति कोई न कोई प्रथम कार्य करता है। जैसे कोई उठते ही कुल्ले करता है, कोई पानी पीता है कोई इधर उधर घूमता है कोई पृथ्वी को प्रणाम करता है कोई अपने मां-बाप को प्रणाम करता है कोई ब्रश करता है कोई बिना कुछ कहे घूमने निकल जाता है। बच्चे कोई हंसते हुए उठते हैं तो कोई उठते ही रोने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी दिनचर्या किसी न किसी एक निश्चित कार्य से शुरू होती है। इसी प्रकार जीवन के अच्छे या बुरे काम में कुछ न कुछ प्रथम होता है शुभ काम में श्री गणेश और दुर्घटना में फर्स्ट एड होता है। जब भी कोई हादसा होता है चाहे वह कितना ही बड़ा हो, उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रहता है। इस बॉक्स में कोई पट्टी या दवाई नहीं होती, बल्कि इसमें लिखा होता है जांच कमेटी का गठन! हमारे देश में यह पक्की व्यवस्था है कि कैसा भी घोटाला हो हादसा हो सबसे पहले जांच कमेटी का गठन होता है। पिछले दिनों नदियों में नाव डूबना, कोचिंग सेन्टर के बेसमेंट में पानी भर गया था, बच्चे डूब गए, जांच कमेटी बैठ गई। आज भी कई कोचिंग सेन्टर बेसमेंट में चल रहे हैं। न कोई सिस्टम बदला न सुनाई दिया कि जांच के बाद दोषियों को सजा हुई। कहीं कार्यक्रमों में कोई टेंट गिर जाता है, आग लग जाती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उनमें कानूनी कार्रवाई के बजाए सबसे पहले जांच कमेटी या उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाता है। जो अधिकारी-कर्मचारी उसमें फंसता दिखाई देता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उच्च स्तरीय जांच एवं सस्पेंड करने की कार्यवाही उस घटना का इलाज नहीं होता है बल्कि आमजनता को शांत करने का एक हथियार है जिससे मामला नेपथ्य में चला जाता है। और जिस व्यक्ति पर घटना का आरोप लगता है उसे सस्पेंड के नाम पर छुट्टियों पर भेज दिया जाता है वह आराम से सैर-सपाटे करता है और आधी या जो भी सस्पेंड समय की तनख्वाह होती है उसे प्राप्त करता रहता है। इस दौरान वह अन्य कार्य भी कर लेता हो तो उसकी कोई जांच नहीं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या निकलता है उसका आमजनता को पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद सस्पेंड कर्मचारी भी बहाल हो जाता है उसे वेतन का शेष पैसा भी इकट्ठा मिल जाता है। सस्पेंड की बहाली के बाद उसे अन्य जगह कोई अच्छी नियुक्ति मिल जाती है। हो गई उसकी तो बल्लै-बल्लै। इस तरह एक हादसे का अध्याय बंद होता है। उसके कुछ समय बाद दूसरा घटनाक्रम तैयार रहता है। एक हादसा धुंधला पड़ता है दूसरा तैयार। ऐसे हादसों के दोषियों को जेल नहीं, फर्स्ट एड से ठीक कर दिया जाता है। उन्हें सजा नहीं मिलती है। सजा तो गरीब की किस्मत में होती है जो छोटे-छोटे अपराधों में जेल काटते हैं।

shivdayalmishra@gmail.com

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित

संवेदनशील मामलों की हो त्वरित जांच-मुख्यमंत्री

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गत ढाई वर्षों में उठाए गए कदमों के कारण अनुसूचित जाति और जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में ऐसे प्रकरणों में लगभग 28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कहा कि एससी-एसटी वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोरता से कार्रवाई की जाए और समाज में समरसता का वातावरण बनाने में सहयोग करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए।

प्रकरण निस्तारण का औसत समय 128 दिन से घटकर हुआ 53 दिन

वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार के दर्ज प्रकरणों में 15.8 % तथा वर्ष 2025 के पहले 6 माह की तुलना में वर्ष 2026 में 15.49% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में से 35.16% का निस्तारण 60 दिन में किया जा रहा था, जो 2025 में बढ़कर लगभग 47% और जुलाई, 2026 तक 67.88% हो गया है। वहीं, प्रकरणों के निस्तारण का औसत समय 128 दिन से घटकर 53 दिन रह गया है। एफआर लगे प्रकरणों में अब 10% के स्थान पर 20% का रैंडम सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो एससी-एसटी वर्ग पर अत्याचार के मामलों में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के 60 दिवस की निर्धारित अवधि में निस्तारण में भी पहले की तुलना में काफी तेजी आई है। लगभग 68% प्रकरणों का निस्तारण 60 दिन में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 पुलिस जिलों में एससी-एसटी सेल स्थापित किए जा चुके हैं एवं शेष 6 पुलिस जिलों में भी एससी-एसटी सेल शीघ्र स्थापित होंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विरुद्ध होने वाले अपराधों में दोष सिद्धि की दर में और अधिक सुधार के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रपति की यूरोपीय यात्रा, यात्रा के दूसरे चरण में नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचीं

नई दिल्ली @ जागरूक जनता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की यूरोपीय यात्रा पर है। द्रौपदी मुर्मू यात्रा के दूसरे चरण में नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचीं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा से मुलाकात करेंगी।

4 से 6 दिसंबर तक जयपुर में होगा लोकमंथन-2026

जयपुर @ जागरूक जनता। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 'भारत का संविधान और भारत का लोकजीवन' की थीम को लेकर आगामी चार से छह दिसंबर को लोकमंथन-2026 का आयोजन किया जायेगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में यहां पर्यटन भवन में कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

NEET पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा...

दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

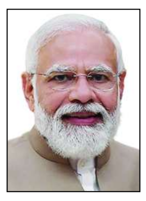

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं है। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगल मिलन बैठक के बाद कही है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले में शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। रिजिजू ने कहा कि बैठक में पीएम ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह केवल केंद्र ही नहीं, बल्कि राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि जहां भी पेपर लीक की घटनाएं हों, वहां कठोर कदम उठाए जाएं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है कि जब नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को सीजेपी ने संसद चलो मार्च का आयोजन किया था। वहीं सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी।

HBOT जीवन रक्षक प्रणाली द्वारा इलाज

ऑक्सीजन (प्राणवायु) ट्रीटमेंट

- »मस्तिष्क चोट, पक्षाघात/लकवा
- »सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म
- »असाध्य घाव/शुगर के घाव
- »कैंसर (रेडियो थेरेपी) के साईड इफेक्ट
- »अचानक बहरापन (Hearing Loss)
- »डाईबेटिक फुट में अम्पुटेशन (पैर कटने) से बचाव

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
98290-17133, 70737-77133
9983317133

डॉ. हिमांशु अग्रवाल M.B.B.S. M.D.

नेशनल हायपरबैरिक रिसर्च सेन्टर
594-B-C, जेम्स कॉलोनी, सैक्टर-3, मंदिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर

Dept. of Hyperbaric Medicine
Fortis Escorts Hospital
JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur

E-mail : hbotjaipur@gmail.com
www.nationalhbot.in

K.R. MANGALAM UNIVERSITY

(Recognized by UGC & Member of AIU)

ACCREDITED WITH GRADE A NAAC

No.1 UNIVERSITY in Haryana amongst all B-Schools as per Times School survey 2026 by The Times of India Optimal Media Solutions Survey

Thanks for making us the... MOST PREFERRED UNIVERSITY

8 LAKH+ CUET REGISTRATIONS for UG & PG Programmes till 2025

FOR ACADEMIC SESSION (2026-27)
KRMU offers SCHOLARSHIPS based on CUET Score/Percentile

CUET -1 (On the Basis of Percentage of Best 4 Subjects Score)

Eligibility Criteria	Scholarship
90% & above	100%
75% to less than 90%	50%
60% to less than 75%	35%
50% to less than 60%	25%
45% to less than 50%	10%

CUET -2 (On the Basis of Average Percentile of Best 4 Subjects)

Eligibility Criteria	Scholarship
95 Percentile and above	100%
85 Percentile to less than 95 Percentile	35%
70 Percentile to less than 85 Percentile	25%
50 Percentile to less than 70 Percentile	10%

Note: Either Percentage (CUET 1) or Percentile (CUET 2) will be considered

ENROLL TODAY & Get a Chance to Gain Remarkable International Exposure
100% SPONSORED* STUDY TOUR TO EUROPE

ADVANCED PROGRAMMES

Engineering & Technology
- B.Tech. (CSE) - AI & ML/Full Stack Development/UX/UI/Cyber Security/Data Science/Robotics & AI
- B.Tech. CSE
- BCA - AI & Data Science/Cyber Security
- BCA (Hons. / Hons. with Research) - AI & Data Science/Cyber Security
- B.Sc. (Hons.) - Computer Science/Cyber Security/Data Science
- MCA/MCA - (AI & ML)

Legal Studies
- BBA LL.B. (Hons.) • B.A. LL.B. (Hons.)
- LL.B. (Hons.) • LL.M.

Liberal Arts
- B.A. (Hons.) - English/Economics/Psychology/Political Science
- B.A. (Hons. / Hons. with Research) - English/Economics/Psychology/Political Science
- B.A. Programme
- M.A. - Applied Psychology

Architecture and Design
- B. Arch • BFA • B.Des. (Hons. / Hons. with Research) - Fashion Design/Interior Design/Game Design & Animation/UX/UI & Interaction Design

Basic and Applied Sciences
- B.Sc. (Hons. / Hons. with Research) - Physics/Chemistry/Maths/Forensic Science
- B.Sc. (Hons.) - Forensic Science
- Integrated/Dual Degree B.Sc. - M.Sc. (Forensic Science)
- M.Sc. - Forensic Science/Part-Time

Agricultural Sciences
- B.Sc. (Hons.) - Agriculture

Education
- B.El.Ed. • B.Ed

Physiotherapy & Rehabilitation Sciences
- Bachelor of Physiotherapy (BPT)

Management & Commerce
- BBA - HR/Marketing/Finance/IB/Travel & Tourism/Business Intelligence & Analytics/Entrepreneurship/International Accounting and Finance/Logistics and Supply Chain Management/Digital Marketing
- BBA (Hons. / Hons. with Research) - HR/Marketing/Finance/IB/Travel & Tourism/Business Intelligence & Analytics/Entrepreneurship/International Accounting and Finance/Logistics and Supply Chain Management/Digital Marketing
- BBA / BBA (Hons. / Hons. with Research) Semester Abroad Programme with the University of East Anglia (UEA), Norwich, UK - HR/Marketing/Finance/International Business/Travel & Tourism
- B.Com. (Hons.)
- B.Com. (Hons. / Hons. with Research)
- B.Com. (Hons.) - International Accounting and Finance
- B.Com. (Hons. / Hons. with Research) - International Accounting and Finance
- B.Com. Programme
- B.Sc. (Hons.) Finance - (Quantitative Finance/Actuarial Science)*
- MBA / MBA - Digital Marketing/Fintech
- Integrated BBA+MBA

Medical & Allied Sciences
- D.Pharm. • B.Pharm.
- M.Pharm. - Pharmaceutics/Pharmacology

Emerging Media & Creator Economy
- B.A. - (Journalism and Mass Communication)
- B.A. (Hons. / Hons. with Research) - (Journalism and Mass Communication)
- M.A. - (Journalism and Mass Communication)
- Ph.D. (All Disciplines)

*Subject to Approval

Lateral Entry & Migration are Also Available

HIGHER EDUCATION SUMMIT & AWARDS 2026 For Distinguished University Leadership & Strategic Partnership Award 2026

Education World — Ranked No #1 in Haryana and No #9 in India by the Education World Grand Jury India Higher Education Ranking 2025-26

BW BUSINESSWORLD — Ranked #1 in Haryana and #5 in North India Amongst all Private Engineering Colleges & Universities by BW BUSINESSWORLD Engineering Survey 2025

CAREERS360 — INDIA'S BEST ENGINEERING INSTITUTES

GU GLOBAL UNIVERSITY RANKINGS 2026 in the field of Law and Humanities, Engineering and Technology, Medicine and Life Sciences

Great Place To Work Certified JAN 2026-Jan 2027 INDIA

World Institutional RANKING — INDIA'S FINEST B-SCHOOL RANKING 2026

IOH Institution Of Happiness Certified 2025-26

12K+ Students | 18K+ Strong Alumni Base | 800+ Top Recruiters | 700+ Faculty Members | 56.6 LPA Highest Package

TOP RECRUITERS: Hughes Systique, Sun Pharma, KPMG, Wipro, Indiabulls, ESCE, Paytm, ICICI Prudential, Cipla, IBM, Google, Microsoft

Transport Facility Available Across Delhi-NCR | Separate AC Hostels for Boys and Girls

8800012936 | 8800012937 | 8800012938 | 8800012939 (Admission Office Open On All Days) Sohna Road, Gurugram, Delhi-NCR | www.krmangalam.edu.in

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रसारित | जागरूक जनता www.jagrukjanta.net | बी-132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर-302039 फोन : 0141-3587886 | सम्पर्क करें | विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए 9928022718 jagrukjantanews@gmail.com | समाचार प्रकाशित करवाने के लिए 9829329070 jagrukjantanews@gmail.com

राज उन्नति की सातवीं बैठकः जीरो टॉलरेंस की नीति और विकास कार्यों को मिले गति, 15 हजार 890 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं की समीक्षा

अधिकारी बहाने नहीं, समय पर काम पूरा कर जनता को राहत पहुंचाएं

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास परियोजनाओं को टाइमलाइन में पूरा कर जनता को समय पर लाभ पहुंचाना राज्य सरकार और हर कार्मिक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया कि वे कार्यों में देरी या लापरवाही को लेकर कोई बहाना नहीं बनाएं, बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए विकास कार्यों की गति को तेजी से बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की सातवीं बैठक में सात विभागों की लगभग 15 हजार 890 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पंच गौरव योजना, और ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर की समीक्षा करते हुए यह दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राज उन्नति की गत बैठकों में दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की। उन्होंने जयपुर रिंग रोड (उत्तरी) परियोजना की समीक्षा करते हुए वन विभाग एवं रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुए इस परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान कर शीघ्र कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना जयपुर में यातायात दबाव कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देकर केन्द्रीय कैबिनेट को अनुमोदन हेतु भिजवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 11 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से बनने वाली जयपुर नॉर्दन रिंग रोड अजमेर हाइवे एनएच-48 (बगरू) से प्रारम्भ होकर जयपुर-दिल्ली एनएच-48 एवं जयपुर-सीकर एनएच-52 से निकलकर जयपुर-बांदीकुई स्पर तक बनेगी।

मुख्यमंत्री ने पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्य सचिव इसकी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी विस्तार की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद हर जिले की आर्थिक समृद्धि के आधार हैं। इस योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर जिले की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। गत वर्ष जिन जिलों में योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का व्यय कम हुआ है, वे अभी से कार्यों को गति प्रदान करें। साथ ही, प्रत्येक जिले में चिन्हित पंच गौरवों (उपज, उत्पाद, वनस्पति प्रजाति, पर्यटन स्थल एवं खेल) के समग्र विकास, संवर्धन और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने पंच गौरव योजना में कम उपलब्धि वाले जिलों को निर्देश दिए कि वे अपने काम में तेजी लाएं और शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें।

राइजिंग राजस्थान में काम शुरू करने वाले निवेशकों का होगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने रेलवे की लूणी-समदड़ी-भीलड़ी डबलिंग प्रोजेक्ट, राजसमंद व उदयपुर में नवीन प्रोटीन पशु आहार संयंत्र की स्थापना, कोटपूतली-बहरोड़ में बायोगैस प्लांट की स्थापना सहित राइजिंग राजस्थान समिट से संबंधित निवेश एमओयू की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत जिन निवेशकों ने एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिया है, उनका एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया जाए। साथ ही, अन्य निवेशकों को भी जल्द कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिले और रोजगार के अवसरों का सृजन हो।

दिसंबर तक सुनिश्चित करें रिम्स का लोकार्पण

उन्होंने एम्स दिल्ली की तर्ज पर आरयूएचएस को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में विकसित करने के काम में आ रही व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरयूएचएस में 13 विभागों की सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर 750 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रथम चरण में यहां इस वर्ष के अंत तक लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, सीटीवीएस विभागों की सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इस संस्थान के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। दिसंबर माह तक इस संस्थान का लोकार्पण किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अग्रणी राष्ट्र बन रहा भारत

पूरी दुनिया में पहुंची भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य हनुमान कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी गोविन्द देव गिरी जी महाराज जैसे संतों के सान्निध्य में होने वाले धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मकता और उच्च संस्कारों का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज अमृत काल में है और दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के रूप में उभर रहा है।

स्वामी विवेकानंद जी ने जिस सांस्कृतिक वैभव का सपना देखा था, आज हमारी संस्कृति उसी रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार नए भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए कहा कि लंबे इंतजार के बाद जब प्रभु राम की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, तो पूरी दुनिया उस पल की साक्षी बनी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण का कार्य निरन्तर कर रही है। खाटूश्याम जी, गिरराज जी और पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक केंद्रों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का वैदिक परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का वाचन कर रहे बटुकों के वैदिक मंत्रोच्चार का श्रवण किया। हनुमान कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भक्तिभाव में सराबोर नजर आए। इस अवसर पर विधायक बालमुकुंद आचार्य, ठाकुर गोविन्ददेव चतुर्वेद विद्यापीठ के न्यासी संदीप झंवर सहित अन्य पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

मालपुरा में तिलहन, खाद्य तेल एवं रिफाइंड चीनी कारोबार में करोड़ों के संदिग्ध कर अपवंचन का खुलासा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा-तृतीय ने इंटेलिजेंस इनपुट और विश्लेषणात्मक डाटा के आधार पर टोंक जिले के मालपुरा में संचालित तिलहन, खाद्य तेल एवं रिफाइंड चीनी के कारोबार से जुड़ी 4 प्रमुख व्यावसायिक फर्मों पर व्यापक सर्च एवं जब्ती की कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में इन फर्मों द्वारा माल के वास्तविक परिवहन के बिना बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास करने और कर अपवंचन किए जाने के संकेत मिले हैं। जिससे राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

सर्च के दौरान संबंधित कारोबारी दस्तावेजों का लेखा पुस्तकों से संतोषजनक सत्यापन नहीं हो सका। इसके बाद विभागीय टीम ने महत्वपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड, बिल बुक, रजिस्टर तथा लैपटॉप सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विस्तृत जांच के लिए जब्त कर लिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि चारों व्यावसायिक फर्मों का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इन फर्मों के लगभग 6.56 करोड़ रुपये के कर संबंधी संव्यवहार संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है। विभाग ने बताया कि जब्त किए गए दस्तावेजों एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा की गहन स्क्रूटनी जारी है। जांच पूरी होने के बाद फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वास्तविक कारोबार तथा कर अपवंचन की सही मात्रा का खुलासा हो सकेगा।

बीसलपुर के पीले पानी पर सरकार कराएगी हाईटेक स्टडी, वैज्ञानिक बताएंगे वजह

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। बीसलपुर बांध से जयपुर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए सरकार सालाना 66 करोड़ खर्च करती है लेकिन इसके बावजूद भी यदि पीले पानी की सप्लाई हो तो पेयजल उपभोक्ताओं के मन में सवाल तो उठेंगे ही। अब इन सवालों पर विराम लगाने के लिए राज्य सरकार बीसलपुर बांध के पानी की स्टडी करवाएगी, जिसमें बांध की सतह पर जमने वाली संभावित हानिकारक काई और पीले पानी की रोकथाम का उपायों का अध्ययन होगा। इसके लिए पीएचईडी ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभागाध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। जल्द ही वनस्पति विभाग बीसलपुर बांध के पानी में जमने वाली काई के सैंपल लेकर उसकी स्टडी करेगा। एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि पीले पानी की सप्लाई फिर से ना हो, इसलिए इसकी स्टडी करवाएगी जा रही ताकि इस पर लगाम लग सके। जी मीडिया ने पीले पानी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब सरकार इसका अध्ययन करवाएगी।

इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे

1. पानी में शैवालों यानी काई को आईडेन्टीफाई किया जाएगा।
2. संभावित हानिकारक या विषाक्त शैवालो की पहचान होगी।
3. नियमित निगरानी के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था के सुझाव मांगे जाएंगे। काई की मात्रा या उसके प्रकारों को निगरानी के लिए तकनीकी सुझावों पर स्टडी।
4. काई के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए किस तरह के वैज्ञानिक तकनीक से रोका जा सके।

कब-कब हुई पीले पानी की सप्लाई

पहली बार बीसलपुर बांध के ट्रीटेट पीले पानी की सप्लाई 2017 में हुई। जब सरकार और इंजीनियर्स को हैरानी हुई कि पूरे शहर में पानी की सप्लाई पीली कैसे हो गई। इसके बाद 2022 में फिर से पीले पानी की सप्लाई हुई तो हचलच तेज हुई। तब भी विभाग ने केमिस्ट से स्टडी तो करवाई लेकिन लगाम नहीं लग पाई। इसके 4 वर्ष बाद इसी साल 2026 में फिर पीले पानी की सप्लाई हुई तो जयपुर के साथ-साथ इंजीनियर्स की बेचैनी बढ़ गई। पीएचईडी के केमिस्ट की हर बार की स्टडी में यही पाया कि मौसम की उथल-पुथल के कारण ऐसा हुआ। सैंपल लिए गए, जिसमें पानी शुद्ध पाया गया।

शुद्ध पानी पर सरकार का खर्चा

सुरजपुरा में सरकार ने ट्रीटेट वाटर प्लांट लगाया हुआ है, जहां बीसलपुर से ट्रीट होकर पानी जयपुर को सप्लाई होता है। पानी को ट्रीटेट करने और जयपुर तक पहुंचाने में 3 करोड़ का बिजली का खर्च हर माह खर्च होता है। इसके अलावा बीसलपुर डेम पर 2.50 करोड़ के बिजली के बिल पर खर्च होता है यानि 5 करोड़ हर महीने खर्च होते हैं। सरकार 1 एमएलडी पानी पर 2570 रुपये खर्च करती है। प्रतिदिन बीसलपुर से 650 एमएलडी पानी ट्रीटेट होता है। इस हिसाब से पानी को ट्रीटेट करने के लिए प्रतिदिन 16,70,500 रुपये, प्रतिमाह 5,01,15000 रुपये और सालाना 60,13,80,000 रुपये खर्च होते हैं। अब सवाल ये है कि जब पानी को ट्रीटेट करने और जयपुर तक पहुंचाने के लिए 60 करोड़ खर्च कर रही है तो पीले पानी की सप्लाई क्यों हो रही है? अब इसी सवाल पर स्टडी होगी और फिर से पीले पानी की सप्लाई ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए।

डबल इंजन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ शेखावाटी का दशकों पुराना इंतजार

यमुना का जल बनेगा शेखावाटी के उज्जवल और उन्नत भविष्य की नींव

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना का जल शेखावाटी के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बनेगा, जिससे शेखावाटी के सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले विकास, विरासत एवं विश्वास के मॉडल जिले के रूप में उभरेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प और समर्पण शेखावाटी के समग्र विकास की आधारशिला बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सोमवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउण्डेशन ने ऐतिहासिक यमुना जल समझौते को लेकर अभिनन्दन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल सुरक्षा से लेकर आधुनिक सड़क नेटवर्क, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तक प्रत्येक क्षेत्र में योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं।

भागीरथी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का हुआ अभिनन्दन

मुख्यमंत्री ने कार्यक्र म में मंत्रोच्चार के बीच प्रतीकात्मक रूप से यमुना जल से भरा कलश शेखावाटी अंचल के लोगों को समर्पित किया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों द्वारा ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के लिए मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया गया। साथ ही, महिलाओं ने भी पारंपरिक वेशभूषा में मंगलगीत के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

संवाद, समर्पण और समन्वय से शेखावाटी पहुंचेगा यमुना का जल

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने यमुना जल समझौते को साकार किया है। इस समझौते से लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से लगभग 1917 क्यूसेक यमुना जल शेखावाटी तक पहुंचेगा। इससे सीकर, झुंझुनूं और चूरू सहित व्यापक क्षेत्र के करीब 75 लाख लोगों को स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के विकास का सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा पानी रहा। वर्ष 1994 में यमुना जल बंटवारे का समझौता हुआ था, लेकिन राजस्थान को उसके अधिकार का पानी नहीं मिला। इस विषय पर हमारी सरकार ने संवाद, समर्पण और समन्वय की रणनीति पर काम किया। इसी का परिणाम है कि तीन दशकों से लंबित यमुना जल समझौता केवल ढाई वर्षों में ही मूर्त रूप ले रहा है।

हवेलियों का हो रहा कायाकल्प

उन्होंने कहा कि शेखावाटी की पहचान उसकी भव्य हवेलियों, विश्वप्रसिद्ध भित्ति-चित्रों और अद्भुत स्थापत्य कला से है। राज्य सरकार ने शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना प्रारंभ कर सीकर, झुंझुनूं और चूरू की 662 ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण तथा पर्यटन उपयोग की कार्ययोजना तैयार की है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हवेलियों के मूल स्वरूप से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शेखावाटी को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे से सीकर, झुंझुनूं और चूरू क्षेत्र के लोगों का दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी राजस्थान के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे परिवहन, उद्योग, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को व्यापक लाभ मिलेगा।

वीरता, उद्यमिता और आस्था की भूमि है शेखावाटी

उन्होंने कहा कि शेखावाटी वीरों, धोरों, संतों, शहीदों एवं भामाशाहों की वीर प्रसूता भूमि है। शेखावाटी के पराक्रमी सपूतों ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में अपने अदम्य साहस की अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के सपूतों ने अपने परिश्रम और व्यापार कौशल से बड़े-बड़े व्यापारिक घराने, कॉरपोरेट संस्थान स्थापित कर देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है। विकट भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां के निवासी मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी, जीण माता, शाकंभरी माता, हर्षनाथ, लोहार्गल, नवलगढ़, मंडावा और डूंडलोद जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केन्द्र हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शेखावाटी की दशकों पुरानी जल आवश्यकता पूरी हुई है, जिससे सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले में विकास की राह प्रशस्त होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को सच्ची श्रद्धांजलि है। शेखावाटी फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री के भागीरथी प्रयासों से शेखावाटी की प्यासी धरती को यमुना का पवित्र जल मिलने से क्षेत्र का समग्र विकास और आने वाली पीढ़ियों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक कालीचरण सराफ, गोरधन वर्मा, हरलाल सहारण, राजेंद्र भांबू, सुभाष मील, गोपाल शर्मा, धर्मपाल गुर्जर, विक्रम सिंह जाखल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भारत ने शनिवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी का बनाया रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचा। हैदराबाद की स्काईरूट एयरोस्पेस का यह रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और अपने साथ नई तकनीक की जांच करने वाले कई उपकरण अंतरिक्ष में ले गया।

भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में स्पेस में धाक

रॉकेट विक्रम-1 का लॉन्च कामयाब

यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है।

450 किमी ऊंचाई तक पेलोड पहुंचाने में सफल रहा।

3D प्रिंटेड इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया है।

2 दोस्तों ने इसरो छोड़कर बनाई कंपनी

- इसे छोटे सैटलाइट कम लागत में अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए तैयार किया गया।
- अंतरिक्ष मलबा हटाने वाली रोबोटिक तकनीक भी परखी गई।
- कंपनी के दोनों संस्थापक पहले इसरो के वैज्ञानिक रहे हैं।

'विक्रम-1' की सफलता भारत की अंतरिक्ष यात्रा का निर्णायक क्षण है।
– नरेन्द्र मोदी, पीएम

स्काईरूट एयरोस्पेस ने खुद बनाकर इसे अंतरिक्ष में भेजा

क्यों खास रहा यह मिशन?

पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी ने ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब तक यह काम मुख्य रूप से इसरो करता था। इससे निजी कंपनियां भी सैटलाइट लॉन्च कर सकेंगी।

इसमें क्या-क्या भेजा गया?

- पीएम मोदी का हाथ से लिखा 'वंदे मातरम्' वाला पोस्टकार्ड अंतरिक्ष भेजा गया।
- वैज्ञानिकों, इंजिनियरों और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के पोस्टकार्ड भी साथ भेजे गए।
- भारत के 3 वैज्ञानिकों डॉ. विक्रम साराभाई, सर सी. वी. रमन और डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां भी भेजी गईं।
- 18 कैरेट सोने से बना छोटा रॉकेट मॉडल भी मिशन का हिस्सा रहा।

निवेश अनुकूलता में 'अग्रणी राज्यों' में शामिल हुआ राजस्थान

राजस्थान के निवेश प्रोत्साहन प्रयासों पर लगी राष्ट्रीय मुहर

नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन

नियमों के सरलीकरण में देश में दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा स्थान

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुहर लगी है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को 'अग्रणी राज्य' की श्रेणी में स्थान मिला है। समग्र रैंकिंग में राज्य देशभर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा। वहीं, बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में राजस्थान ने दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का परिणाम है।

राज निवेश पोर्टलः अब 190 सेवाएं उपलब्ध, निस्तारण समय में आ रही कमी

राज्य में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने, निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने, औद्योगिक भूमि, आधारभूत सुविधाओं तथा निवेश-अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब नीति आयोग की रिपोर्ट में भी दिखाई दिया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में नियामकीय सुगमता के क्षेत्र में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने निवेशकों को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार सुदृढ़ किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोर्टल पर कुल 34,704 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 जून तक कुल 30 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 17 हजार से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। इस अवधि में आवेदनों के निस्तारण की समग्र दर 64 प्रतिशत रही, जबकि सर्वाधिक उपयोग वाली 11 प्रमुख सेवाओं में यह दर 68 प्रतिशत रही। साथ ही, प्रमुख सेवाओं के औसत निस्तारण समय में कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में नए विद्युत कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है, इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है।

पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू

राज्य सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं। इनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल एवं अपैरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एवं डिफेंस जैसी सेक्टर आधारित नीतियां शामिल हैं। साथ ही, इसमें कई ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनके लिए राजस्थान में पहली बार नीतियां बनाई गई हैं। इन्हीं व्यापक नीतिगत सुधारों का परिणाम है कि नीति आयोग ने निवेश प्रोत्साहन के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को देश में तीसरा स्थान दिया है।

राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार हो रहा मजबूत

नीति आयोग के इस सूचकांक की विशेषता यह है कि इसमें केवल सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही मूल्यांकन नहीं किया गया है, बल्कि देशभर के निवेशकों से प्राप्त सुझावों और अनुभवों को भी शामिल किया गया है। इस कारण यह रिपोर्ट निवेशकों की वास्तविक धारणा को भी सामने लाती है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है और राज्य निवेश के लिए अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय तथा उद्योग-अनुकूल गंतव्य के रूप में उभरा है।

राइजिंग राजस्थान समिट से बना सकारात्मक निवेश माहौल

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने प्रदेश में निवेश का नया माहौल तैयार किया है। समिट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते (एमओयू) हुए, जिनमें से करीब 9 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। इन निवेश प्रस्तावों के ि यान्वयन के लिए राज्य सरकार नियमित समीक्षा, विभागों के बीच समन्वय और निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट से बने इसी सकारात्मक निवेश माहौल और सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का प्रतिबिंब नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में भी दिखाई देता है।

विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग ने 'निवेश अनुकूलता सूचकांक' तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2024 में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों के लिए निवेश-अनुकूल ढांचा विकसित करने पर जोर दिया था। इसके बाद केंद्रीय बजट 2025-26 में निवेश अनुकूलता सूचकांक विकसित करने की घोषणा की गई।

दीया कुमारी ने की जयपुर विकास को लेकर सांसद, विधायकों से चर्चा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपने निवास पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य जी एवं सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के साथ बैठक कर जयपुर में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में जयपुर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजधानी के समग्र, सुव्यवस्थित एवं सतत विकास के साथ-साथ आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, नागरिक सुविधाओं का विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एसएलएससी की बैठक में 10 उद्योगों को अनुदान स्वीकृत

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में शुरू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बदौलत प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार अनुदान दिए जा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक हुई। इसमें 10 उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया। इन उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव, थ्रस्ट बूस्टर/ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इन्सेन्टिव जैसे विविध परिलाभ दिए जाएंगे।

मुख्य सचिव की सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था होगी और मजबूत

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को डिजीटल माध्यम से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, हाई रिस्क गर्भवतियों की निगरानी, रेफरल प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग तथा प्रसव सुविधा वाले राजकीय अस्पतालों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पिछले 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में हुए सभी सिजेरियन प्रसव तथा हाई रिस्क गर्भवतियों की स्थिति की अधिकारियों एवं फील्ड स्वास्थ्यकर्मियों से सीधे जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में सभी प्रसव सुरक्षित रहे। इस पर उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को भर्ती सभी प्रसूताओं की सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।

भारतीय सनातन संस्कृति पुनरुत्थान भवन का लोकार्पण

सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भावी पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) तथा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिराई (भोपालगढ़) में आयोजित 'भारतीय सनातन संस्कृति पुनरुत्थान भवन' के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। समारोह में सतगुरु स्वामी सुंदरदासजी महाराज, पाली सांसद पी.पी. चौधरी, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, ओसियां विधायक भैराराम सियोल, उपस्थित रहे। जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिराई आकर वे अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा निरंतर जनकल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संकट अथवा परेशानी आने पर यह ट्रस्ट सदैव आगे बढ़कर जरूरतमंदों की सहायता करता है। समाज के प्रति ट्रस्ट की सेवा भावना और जनकल्याणकारी गतिविधियां सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को सुंदरदासजी महाराज का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। संतों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से समाज में सेवा, सद्भाव, संस्कार और मानवीय मूल्यों को मजबूती मिलती है। दिलावर ने कहा कि अनंत सुखरामजी ट्रस्ट द्वारा भव्य 'भारतीय सनातन संस्कृति पुनरुत्थान भवन' का निर्माण किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा–2026

पशुपतिनाथ दर्शन का सपना सचः नेपाल के लिए पहली हवाई तीर्थ यात्रा रवाना

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत हवाई यात्रा का सोमवार को भव्य आगाज हो गया। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने 43 वरिष्ठ नागरिकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल जयपुर के सिंधी कैंप स्थित होटल महादेव विला से बस द्वारा नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जहां से वे हवाई जहाज से काठमांडू पहुंचेंगे। सभी वरिष्ठ तीर्थयात्री काठमांडू में स्थित प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। पशुपतिनाथ जी के साथ-साथ काठमांडू के अन्य प्रमुख दर्शनीय धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा।

3-स्टार होटल में ठहराव और सुरक्षा

देवस्थान मंत्री कुमावत ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय हमारे बुजुर्गों के जीवन को सुगम और भक्तिमय बनाना है। उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना देखते थे, आज उन्हें सीधे बाबा पशुपतिनाथ के द्वार पहुंचा रही है। मंत्री कुमावत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में कई सुधार किए गए हैं। कुमावत ने बताया कि इस बार हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को उनके ठहराव के लिए 3 स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है।

जवाबदेही लोकतंत्र की रीढ़, पर संतुलन भी जरूरी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

नविता
पत्रकार
@jagrukjanta.net

लोकतंत्र में "सरकार" शब्द का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा है और सेवा का पहला नियम है,सवाल का जवाब देना। आज जब हर नागरिक सोशल मीडिया, RTI और जनसभाओं के जरिए सीधे सवाल पूछ सकता है, तो यह बहस और जरूरी हो गई है.सरकार को जनता के प्रति कितना और कैसे जवाबदेह होना चाहिए?

सरकार की जवाबदेही क्यों जरूरी है?

जनता प्रजा नहीं है अब, टैक्स जनता देती है, वोट जनता देती है। इसलिए नीतियों, खर्च और नाकामी पर सवाल पूछना जनता का अधिकार है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सेवाओं में खामी है तो सरकार को कारण और समाधान दोनों बताने चाहिए।

पारदर्शिता से भ्रष्टाचार घटता है: जब हर फैसला और खर्च सार्वजनिक होता है तो मनमानी की गुंजाइश कम होती है। CAG रिपोर्ट, संसदीय समितियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जवाबदेही के उपकरण हैं।

भरोसा बनता है: कोविड, नोटबंदी या किसी परीक्षा में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार समय पर आकर तथ्य रखे तो अफवाहें और असंतोष अपने आप कम होते हैं। चुप्पी से अविश्वास बढ़ता है।

सुधार का रास्ता खुलता है: जनता की शिकायतें ही नीति सुधार का फीडबैक हैं। किसान, छात्र, व्यापारी - सबकी आवाज सुने बिना कोई योजना जमीन पर सफल नहीं हो सकती।

जवाबदेही के साथ संतुलन भी जरूरी क्यों?

निर्णय लेने की स्वतंत्रता: हर छोटे फैसले पर सफाई देने में सरकार का समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या आर्थिक सुधार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तुरंत सब कुछ सार्वजनिक करना संभव नहीं होता।

जिम्मेदारी का बोझ: मंत्री और अधिकारी 24x7 जनता को जवाब देते रहें तो नीति बनाने और लागू करने का काम कौन करेगा? जवाबदेही का मतलब 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि तय समय पर तय मंच पर जवाब है।

राजनीतिकरण का खतरा : हर मुद्दे को इस्तीफे की मांग बना देने से प्रशासन ठप हो सकता है। एक गलती पर पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा करना समस्या का हल नहीं, बाधा बन जाता है।

संस्थाओं की भूमिका: संसद, न्यायपालिका, CAG, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं पहले से जवाबदेही के लिए बनी हैं। सरकार को सीधे हर व्यक्ति को जवाब देने के बजाय इन संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए।

बीच का रास्ता क्या हो?

जवाबदेही का मतलब "हर सवाल का तुरंत उत्तर" नहीं है। इसका मतलब है "तय प्रक्रिया से तय समय में जवाब"।

संसद: सबसे बड़ा मंच। हर मंत्री को सदन में सवालों का जवाब देना चाहिए और समकक्षों को जवाब देने मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याने की बोलने वाले को पूरी बात बोलने का मौका मिले।

डिजिटल डैशबोर्ड : सरकारी योजनाओं का खर्च, प्रगति ऑनलाइन हो ताकि जनता खुद देख सके।

समयबद्ध जांच: किसी गड़बड़ी पर तय दिनों में रिपोर्ट और कार्रवाई सार्वजनिक हो। सरकार कोई कंपनी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट-लॉस देखे। न ही जनता कोई ग्राहक है जिसे हर बात पर "हम देख रहे हैं" कहकर टाल दिया जाए।

लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सरकार सवालों से न घबराए और जनता आरोपों से पहले तथ्य मांगे।

सरकार को जनता के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपलब्ध होना चाहिए-
यह मांग भी उतनी ही जरूरी है जितनी यह बात कि जवाबदेही का मतलब शासन को ठप करना नहीं।

आखिर में, सरकार भी हमारी है और सवाल भी हमारे हैं। दोनों के बीच संवाद की खिड़की खुली रहे, बस यही लोकतंत्र की असली जीत है।

निजी विद्यालयों की मान्यता एवं लंबित आवेदनों के निस्तारण संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित

31 से खुलेंगे निजी विद्यालयों की नवीन मान्यता के आवेदन

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा। नवीन मान्यता के लिए आवेदन 31 जुलाई से आमंत्रित किए जाएंगे तथा प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निजी विद्यालयों को सरकारी नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री शिक्षा संकुल में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया के सरलीकरण तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में निर्देश दे रहे थे। श्री दिलावर ने नवीन मान्यता आवेदनों की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रथम स्तर पर गठित समिति 7 दिवस के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट का परीक्षण कर उसे अग्रेषित करेंगे। अंतिम निर्णय निदेशक स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी। समिति के गठन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के अनुरूप होगी। यदि कोई जांच अधिकारी अनावश्यक विलंब करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में पाई गई प्रत्येक कमी का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा तथा आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही बच्चों की सुरक्षा एवं नियमों के सरलीकरण के लिए आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यालयों में छात्रों के बैठने की व्यवस्था, प्रार्थना सभा, भवन, कक्षों, आवागमन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को विद्यालय परिसर के बाहर वाहन से न उतारा जाए, बल्कि सुरक्षित रूप से परिसर के भीतर ही उतारा जाए। उन्होंने निजी विद्यालयों की मान्यता से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर उनकी मान्यता भी निरस्त की जा सकेगी। दिलावर ने कहा कि जिन विद्यालयों में डमी विद्यार्थियों की प्रवृत्ति पाई जाएगी अथवा विद्यालय समय में विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सम्पादकीय

नई यूरिया नीति ही काफी नहीं, सब्सिडी सुधार अब भी जरूरी

नई राष्ट्रीय यूरिया नीति कृषि क्षेत्र से जुड़े इस महत्वपूर्ण कच्चे माल से जुड़ी समस्या का आंशिक समाधान प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है ताकि इसे वैश्विक आपूर्ति झटकों से बचाया जा सके। भारत अपनी वार्षिक 4 करोड़ टन यूरिया मांग का 25 फीसदी आयात करता है। पश्चिम एशिया युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद जब तक चीन ने अपना अस्थायी निर्यात प्रतिबंध नहीं हटाया तब तक कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गईं। नीति का लक्ष्य 8 या 9 यूरिया संयंत्र स्थापित करना है जिनकी उत्पादन क्षमता 1 करोड़ टन होगी। यानी वर्तमान में आयात की जाने वाली मात्रा के समतुल्य। इसके लिए प्रोत्साहन संरचना में बदलाव किए गए हैं। इनमें स्थिर और परिवर्तनीय लागतों को अलग करना, इक्विटी पर रिटर्न की गणना के लिए 12-16 फीसदी का बैंड लागू करना और विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा विनिमय दर के आधार? पर स्थिर लागतों को चार साल बाद रुपये में बदलना शामिल है। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य निस्संदेह एक तात्कालिक समस्या का समाधान करता है क्योंकि निकट भविष्य में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। लेकिन जब भारत की उर्वरक नीति की गहरी संरचनात्मक समस्याओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह अपर्याप्त प्रतीत होता है। मूल समस्या भारत की उर्वरक सब्सिडी संरचना में है जो अमोनिया-आधारित यूरिया (एन) को फॉस्फेट आधारित (पी) और पोटैशियम आधारित (के) पोषक तत्वों पर प्राथमिकता देती है। जहां बाद के दोनों पोषक तत्वों पर सब्सिडी पोषक तत्व सामग्री के आधार पर दी जाती है वहीं यूरिया पर सपाट दर से सब्सिडी दी जाती है। वर्तमान में किसान 45 किलो का यूरिया बैग 242 रुपये में खरीदता है जबकि सरकार को इसकी लागत 2,200 रुपये से 4,000 रुपये तक आती है। यह इस पर निर्भर करता है कि यूरिया घरेलू रूप से निर्मित है या आयातित। आश्चर्य नहीं कि वर्षों में यूरिया सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक बन गया है जिससे वार्षिक सब्सिडी अस्थिर स्तर तक पहुंच गई है। आमतौर पर यूरिया ही उर्वरक सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद वैश्विक कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह आंकड़ा काफी अधिक होने की संभावना है। अधिक घरेलू संयंत्र स्थापित करना आयात पर निर्भरता को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन अन्य समस्याओं पर भी विचार करना आवश्यक है। पहला, सरकार का अनुमान है कि यूरिया की मांग हर साल 5 फीसदी बढ़ रही है। एक यूरिया संयंत्र बनाने में लगभग दो साल लगते हैं। मान लें कि सभी नए संयंत्र समय पर बनकर 1 करोड़ टन उत्पादन शुरू कर दें यानी वर्तमान घरेलू कमी के बराबर, तब भी भारत मांग के ग्राफ से पीछे ही रहेगा। यह स्थिति 2012 की पहली यूरिया नीति में भी स्पष्ट थी जिसके तहत छह नई इकाइयां स्थापित की गईं लेकिन आयात जारी रहा। दूसरा, यूरिया संयंत्र में विदेशी मुद्रा जोखिम परिवर्तनीय लागतों से आता है, विशेष रूप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से, जो फीडस्टॉक और ऊर्जा स्रोत दोनों है और उत्पादन लागत का 60 से 80 फीसदी हिस्सा बनाती है।

आर्थिक वातावरण में उच्च स्तर की अनिश्चितता पूर्वानुमान को बेहद कठिन बना देती है। आरबीआई फिलहाल मुद्रास्फीति के अनुमान को बरकरार रख सकता है और अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर सकता है। नीतिगत कार्रवाई के संदर्भ में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखना ही उचित होगा।

तेल और मॉनसून बढ़ा सकते हैं नीतिगत चुनौतियां

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

नंद किशोर वर्मा
लेखाकार
@jagrukjanta.net

> जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4 फीसदी के लक्ष्य को पार कर गई। ऐसा जनवरी 2025 के बाद पहली बार हुआ है।

जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4 फीसदी के लक्ष्य को पार कर गई। ऐसा जनवरी 2025 के बाद पहली बार हुआ है। बीते दिनों जारी आंकड़ों के अनुसार, जून में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 4.38 फीसदी हो गई, जबकि उससे पिछले माह यह 3.93 फीसदी थी। मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई। खाद्य मूल्य सूचकांक में 5.32 फीसदी की वृद्धि हुई। कोर यानी मुख्य मुद्रास्फीति दर लगभग 4 फीसदी रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)अगस्त की शुरुआत में नीतिगत समीक्षा करेगी। उसके पास जून माह के नवीनतम मुद्रास्फीति आंकड़े उपलब्ध होंगे। हालांकि समग्र आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक नहीं है, लेकिन एमपीसी की बैठक में मौजूदा व्यापक आर्थिक परिवेश की जटिलता के हावी रहने की संभावना है।

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिये सुलझाने पर सहमति बनने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई थी। भारतीय कच्चा तेल बास्केट की कीमत अप्रैल में औसतन लगभग 114 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर जुलाई में लगभग 71 डॉलर प्रति बैरल रह गई। हालांकि, जैसा कि कई लोगों को आशंका थी, यह नाजुक युद्धविराम टिक नहीं सका और पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों के बीच हमले जारी हैं। इसके परिणामस्वरूप, होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है। वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20 फीसदी इसी जलमार्ग से गुजरता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि यह ईरान को छोड़कर सभी देशों के लिए खुला रहे, लेकिन इसके लिए शुल्क लिया जाएगा। सुरक्षा प्रदान करने के बदले में अमेरिका द्वारा प्रतिपूर्ति की मांग करना अपने आप में एक समस्या है और इसके व्यापक भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं। इसके अलावा,

जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक के 4 फीसदी के लक्ष्य को पार कर गई। ऐसा जनवरी 2025 के बाद पहली बार हुआ है।

इस संघर्ष ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि ईरानी हमलों को रोकना आसान नहीं होगा। ईरान ने क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों को अपनी मर्जी से निशाना बनाया है।

इसलिए, जब तक दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाते, तब तक होर्मुज स्ट्रेट से आपूर्ति का स्तर अनिश्चित बना रहेगा, जिससे निकट भविष्य में तेल की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। भारत ने कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का खुदरा पेट्रोल की कीमतों पर आंशिक प्रभाव ही डाला है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से मजबूती आने के साथ, निकट भविष्य में खुदरा ईंधन की कीमतों में गिरावट की संभावना को आसानी से नकारा जा सकता है। इस प्रकार, यह मुद्रास्फीति दर पर दबाव डालना जारी रखेगा और पूर्वानुमानों में इसे ध्यान में रखना आवश्यक होगा। खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही है और बारिश में लगभग 18 फीसदी की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप खरीफ की बोआई में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि भारत में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, लेकिन खरीफ उत्पादन में भारी गिरावट से खाद्य मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगी, जिसका एक कारण जल्द खराब होने वाले उत्पादों की कीमतों में वृद्धि भी है। इसका प्रभाव रबी फसलों पर भी पड़ सकता है।

इसलिए, उम्मीद से कमजोर मॉनसून से नीतिगत जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। केंद्रीय बैंक आमतौर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, कमजोर मॉनसून के कारण बढ़ी हुई कीमतें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। एमपीसी की जून बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति दर 5.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। आर्थिक वातावरण में उच्च स्तर की अनिश्चितता पूर्वानुमान को बेहद कठिन बना देती है। आरबीआई फिलहाल मुद्रास्फीति के अनुमान को बरकरार रख सकता है और अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर सकता है। नीतिगत कार्रवाई के संदर्भ में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखना ही उचित होगा। ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना तभी बनेगी जब मुद्रास्फीति के अनुमान मौजूदा अनुमानों से काफी अधिक बढ़ जाएंगे, जिसकी फिलहाल गुंजाइश नहीं लग रही है। बहुत कुछ पश्चिम एशिया की स्थिति और मॉनसून की प्रगति पर निर्भर करेगा।

महंगाई, मध्यम वर्ग और बदलती उपभोक्ता संस्कृति

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

राम शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

आज भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भारत को आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन मान रही हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगभग 6.6 प्रतिशत रखा है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर मानी जा रही है। इसके बावजूद आम नागरिक, विशेषकर मध्यम वर्ग, के सामने सबसे बड़ी चिंता आज भी महंगाई है। आर्थिक विकास के आँकड़े जितने उत्साहजनक दिखाई देते हैं, रसोई का बजट उतना ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। यही विरोधाभास आज के भारत की सबसे बड़ी आर्थिक वास्तविकता है।

जून 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुँच गई, जो लगभग डेढ़ वर्ष बाद पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही। यह आँकड़ा बताता है कि महंगाई अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है। खाद्य पदार्थों, फल-सब्जियों, दालों, खाद्य तेल, दूध तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव आम परिवारों की मासिक आय पर पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसकी आय महंगाई की गति से नहीं बढ़ रही, जबकि खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

महंगाई केवल बाजार में वस्तुओं के महंगे होने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव परिवारों की जीवनशैली, बचत, निवेश और भविष्य की योजनाओं पर पड़ता है। आज एक मध्यमवर्गीय परिवार की आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, मकान के किराए या गृह ऋण की किस्त, बिजली-पानी, परिवहन और दैनिक आवश्यकताओं पर खर्च हो जाता है। निजी विद्यालयों की बढ़ती फीस, अस्पतालों में इलाज का बढ़ता खर्च और महानगरों में मकानों की ऊँची कीमतों ने मध्यम वर्ग के आर्थिक संतुलन को प्रभावित किया है।

विडंबना यह है कि भारत का मध्यम वर्ग न तो गरीबों की तरह सरकारी सहायता योजनाओं का व्यापक लाभ उठा पाता है और न ही उच्च आय वर्ग की तरह महंगाई का प्रभाव आसानी से सहन कर सकता है। आयकर का बड़ा हिस्सा भी यही वर्ग देता है और उपभोग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति भी यही प्रदान करता है। इसलिए मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति का सीधा प्रभाव देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक बड़ा आधार घरेलू उपभोग है। यदि मध्यम वर्ग खर्च कम करने लगता है, तो उद्योगों, व्यापार और सेवा क्षेत्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री महंगाई को केवल मूल्य वृद्धि नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक मानते हैं।

नीट: अब सीट की जंग में काउंसलिंग युद्ध

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

डॉ. मोनिका शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

री नीट-2026 का रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इस वर्ष देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक वन हासिल की है। राजस्थान के उपलक्ष्य को तीसरी रैंक मिली है। हर कोई अब इस गणित में उलझा है कि उसको अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इसके लिए अभिभावकों के सामने अब प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराना बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहेगा कि उसके बच्चे को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। इसके लिए उसे काउंसलिंग बहुत सावधानी से करनी होगी।

पेरेंट्स को चाहिए कि वह पिछले दो सालों की रैंक देख लें कि किस रैंक पर कौनसा कॉलेज मिला है। इसके आधार पर वह प्री तैयारी कर लें। इससे उसका काम काफी आसान हो जाएगा। हालांकि इस बार नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देश में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाकर 1,36,939 कर दी है। राजस्थान हमेशा से नीट के लिए एक हाई-मेरिट राज्य रहा है। डाटा के अनुसार, राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 7,205 है। राज्य के सरकारी और सोसाइटी संचालित कॉलेजों को मिलाकर कुल 4,505 सीटें उपलब्ध हैं। इसी तरह से हाल ही में मिली 900 नई प्राइवेट सीटों की मंजूरी के बाद राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजों की सीटें बढ़कर 3600 हो गई हैं। राजस्थान में सरकारी सीट पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, क्योंकि राजस्थान से 1.33 लाख विद्यार्थियों ने नीट क्वालिफाई किया है।

> **जिस गति से एमबीबीएस की सीटें बढ़ रही हैं। इससे यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या एमबीबीएस करना अब सही है। इसके बावजूद समाज और स्वास्थ्य प्रणाली में एमबीबीएस डॉक्टर की उपयोगिता आज भी शीर्ष पर बनी हुई है। बदलते दौर में एमबीबीएस की उपयोगिता इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सा मानव जीवन की रक्षा का एकमात्र जरिया है।**

जिस गति से देश में एमबीबीएस की सीटें बढ़ रही हैं। इससे अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या एमबीबीएस करना अब सही रहता है। इस सबके बावजूद समाज और स्वास्थ्य प्रणाली में एमबीबीएस डॉक्टर की उपयोगिता आज भी शीर्ष पर बनी हुई है। बदलते दौर में एमबीबीएस की उपयोगिता इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सा केवल एक कॅरियर नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा का एकमात्र जरिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार, प्रति एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर होना अनिवार्य है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में यह अनुपात अभी भी ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में बेहद असंतुलित है। आज भी देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों को योग्य एलोपैथिक डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। महामारी के दौर ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा उसकी स्वास्थ्य प्रणाली पर टिकी होती है और उस प्रणाली की रीढ़ की हड्डी एमबीबीएस डॉक्टर ही होते हैं। इसके अलावा, आधुनिक जीवनशैली के कारण बढ़ रही बीमारियों (जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक और मानसिक तनाव) के सटीक इलाज और परामर्श के लिए समाज को हमेशा एक सर्टिफाइड डॉक्टर की जरूरत रहेगी। यह एक ऐसा पेशा है, जिसे कभी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि मरीजों को इलाज के साथ-साथ मानवीय संवेदना और भरोसे की आवश्यकता होती है, जो केवल एक डॉक्टर ही दे सकता है। इसी उपयोगिता के कारण आज भी समाज में एमबीबीएस को लेकर लोगों की सोच बेहद सकारात्मक, लेकिन व्यावहारिक हो चुकी है। जहां एक तरफ इसे आज भी देश का सबसे गरिमापूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक पेशा माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ अब लोग इसके पीछे के मानसिक तनाव और लंबी अवधि को लेकर जागरूक हो रहे हैं। पेरेंट्स अब केवल डॉक्टर टैग के लिए बच्चों पर दबाव बनाने से बच रहे हैं। इसके अलावा, प्राइवेट कॉलेजों की करोड़ों रुपए की फीस और उसके बदले मिलने वाले शुरुआती वेतन (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट) को लेकर लोग काफी व्यावहारिक सोच रखने लगे हैं। इतना जरूर है कि केवल एमबीबीएस (यूजी) डिग्री की वैल्यू वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन अनिवार्य होता जा रहा है। भविष्य में एक सफल डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस के बाद एमडी (एमडी), एमएस (एमएस) या सुपर स्पेशलाइजेशन करना आवश्यक होगा, क्योंकि मरीज क्वालिटी यानी कुशल डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने हाल ही में 25 नए मेडिकल कॉलेजों और 9,911 नई सीटों को मंजूरी दी है, जिसके बाद भारत में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,36,939 हो गई है।

ओपिनियन

हिन्दुस्तान ने अंतरिक्ष में मनवाया अपना लोहा

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

निखलेश कुमार शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है, जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व कर सकता है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण केवल एक रॉकेट की उड़ान नहीं, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास, नवाचार और वैज्ञानिक क्षमता की उड़ान है। इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब केवल सरकारी संस्थानों की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में विश्वस्तरीय उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखता है। यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब पूरी दुनिया भारत की वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी क्षमता और तेजी से बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नजर रखे हुए है।

विक्रम-1 मिशन की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि इसे तैयार करने वाली टीम की औसत आयु केवल 28 वर्ष रही। लगभग एक हजार युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने वर्षों तक अथक परिश्रम कर इस सपने को साकार किया। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि देश के युवाओं की प्रतिभा, समर्पण और नवाचार की शक्ति का प्रमाण है। जिस युवा पीढ़ी को कभी केवल रोजगार तलाशने वाली पीढ़ी माना जाता था, वही आज रोजगार देने वाली कंपनियां स्थापित कर विश्वस्तरीय तकनीक विकसित कर रही है। यह भारत के बदलते स्वरूप और नई सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है।

हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना वर्ष 2018 में इसरो के दो पूर्व वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने एक ऐसा सपना देखा, जिसे पूरा करना आसान नहीं था। सीमित संसाधनों, कठिन तकनीकी चुनौतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच उन्होंने अपने साथ युवा वैज्ञानिकों की टीम तैयार की और आठ वर्षों की निरंतर मेहनत के बाद भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। यह कहानी केवल एक स्टार्टअप की सफलता नहीं बल्कि नए भारत की उद्यमशीलता, आत्मविश्वास और नवाचार की कहानी है।

मिशन "आगमन" के तहत विक्रम-1 ने उड़ान भरने के बाद मात्र 15 मिनट 46 सेकंड में अपने सभी छह पेलोड को पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर निम्न पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह मिशन तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल था क्योंकि किसी भी निजी कंपनी के लिए पहली बार ऑर्बिटल लॉन्च करना बड़ी चुनौती माना जाता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे सफल बनाकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब केवल अंतरिक्ष मिशनों में भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है।

> **28 वर्ष की औसत आयु वाले एक हजार वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई, पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफलता ने दुनिया को दिखाया भारत के नवाचार और आत्मनिर्भरता का नया आकाश**

विक्रम-1 अत्याधुनिक तकनीक से लैस रॉकेट है। इसका मुख्य ढांचा हल्के लेकिन अत्यंत मजबूत कार्बन कंपोजिट से तैयार किया गया है जिससे इसका वजन कम और क्षमता अधिक बनी रहती है। इसके ऊपरी चरण में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित त्रि-आयामी मुद्रित द्रव इंजन का उपयोग किया गया है। यह तकनीक निर्माण समय और लागत दोनों को कम करती है तथा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को अधिक किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने की इसकी क्षमता भारत के लिए अंतरिक्ष व्यवसाय के नए अवसर खोलती है।

इस मिशन के साथ भेजे गए छह पेलोड भी भारत की वैज्ञानिक सोच और नवाचार का परिचय देते हैं। इनमें अंतरिक्ष में रोबोटिक तकनीक का परीक्षण करने वाला उपकरण, भविष्य के उपग्रहों के लिए नई प्रणालियों का परीक्षण करने वाला क्यूबसैट, नई अंतरिक्ष तकनीकों के सत्यापन हेतु परीक्षण उपग्रह, उपग्रह पृथक्करण प्रणाली की जांच करने वाला यंत्र, स्वर्ण और हीरों से निर्मित विशेष अंतरिक्ष कला तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तलिखित संदेश शामिल था। इन पेलोड ने यह दर्शाया कि भारत विज्ञान के साथ संस्कृति, नवाचार और रचनात्मकता का भी सुंदर समन्वय कर रहा है।

इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां निजी कंपनियां स्वयं ऑर्बिटल रॉकेट विकसित कर अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण करने में सक्षम हैं। अब तक यह उपलब्धि मुख्य रूप से अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास थी। भारत का इस सूची में शामिल होना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन की सफलता पर स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए युग की शुरुआत है। उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में और भी बड़े लक्ष्य हासिल करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसे भारत की बढ़ती स्पेस इकोनॉमी और वैज्ञानिक क्षमता का महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि सरकार निजी क्षेत्र और वैज्ञानिक नवाचार को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

आज भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं रहा। यह देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, रक्षा, संचार, कृषि, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों की आधारशिला बन चुका है। निजी कंपनियों की भागीदारी से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नई तकनीकों का विकास होगा, निवेश आकर्षित होगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और देश वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में मजबूत हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेगा।

पंचांग

ज्योतिर्विद् अक्षय शास्त्री

साकेत पंचांग, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता

जागरूक जनता पंचांग, नक्षत्र, तिथि, चौघड़िया

सूर्योदय-सूर्यास्त, तिथि

बुधवार, 22/07/2026

सूर्योदय : 05:50 **सूर्यास्त :** 19:16 **चन्द्रोदय :** 13:29 **चन्द्रास्त :** 24:22 **शक सम्वत :** 1948 पराभव **विक्रम संवत् :** 2083 सिद्धर्थी **अमान्ता महीना :** आषाढ़ा **पूर्णिमांत :** आषाढ़ा **सूर्य राशि :** कर्क **चन्द्र राशि :** तुला **पक्ष :** शुक्ल **तिथि :** नवमी, 31:02 तक **वार :** बुधवार **द्रिक ऋतु :** वर्षा **द्रिक - वैदिक अयन :** दक्षिणायन **कलियुग :** 5127 वर्ष

नक्षत्र, योग, करण

नक्षत्र : स्वाति, 22:59 तक
योग : साध्य, 18:36 तक
प्रथम करण : बालवा, 18:09 तक
द्वितीय करण : कौवाला, 31:02 तक

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त	04:14 ए एम से
प्रात: सन्ध्या	04:35 ए एम से
अभिजित मुहूर्त	कोई नहीं
विजय मुहूर्त	02:44 पी एम से
गोधूलि मुहूर्त	07:17 पी एम से
सायाह्न सन्ध्या	07:18 पी एम से
अमृत काल	01:26 पी एम से
निशिता मुहूर्त	12:7 ए एम, जुलाई 23 से
रवि योग	11:03 पी एम से

निवास और शूल

दिशा शूल : उत्तर में
राहु काल वास दक्षिण-पश्चिम में
होमाहुति : शुक्र
कुंभ चक्र: दक्षिण

चौघड़िया

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
लाभ	05:49 - 07:29	उद्वेग	19:15 - 20:34
अमृत	07:29 - 09:10	शुभ	20:34 - 21:54
काल काल वेला	09:10 - 10:51	अमृत	21:54 - 23:13
शुभ	10:51 - 12:32	चर	23:13 - 00:32
रोग वार वेला	12:32 - 14:13	रोग	00:32 - 01:51
उद्वेग	14:13 - 15:53	काल	01:51 - 03:11
चर	15:53 - 17:34	लाभ	03:11 - 04:30
लाभ	17:34 - 19:15	उद्वेग	04:30 - 05:49

अमृत, शुभ, लाभ और चर को शुभ चौघडिया माना जाता है एवं उदवेग, काल एवं रोग को अशुभ चौघडिया माना जाता है।

आज नवमी

आज कौन सा कार्य करें

नवमी रिक्ता तिथि है इसलिए इस दिन कोई भी नया, मांगलिक कार्य वर्जित है।

बुधवार को क्या करें

बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। यह भगवान गणेश और दुर्गा का दिन है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए।

ये कार्य करें :- सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। बुधवार को दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन जमा किए गए धन में बरकत रहती है। मंत्रणा, मंथन और लेखन कार्य के लिए भी यह दिन उचित है। ज्योतिष, शेयर, दलाली जैसे कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है।

यह कार्य न करें:- उत्तर, पश्चिम और ईशान में यात्रा न करें। बुधवार को धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है।

नोट : शुक्ल पक्ष में एक से पंचमी तक तिथियां अशुभ कही गई हैं, क्योंकि इन तिथियों में चंद्रमा क्षीण बल होता है और चंद्र बल उन दिनों नहीं रहने से कार्य सफल नहीं होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक तिथियों में चंद्र बल क्षीण होने से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।

राशिफल

आषाढ़, शुक्ल, नवमी, 2083 बुधवार, 22 जुलाई - 28 जुलाई, 2026

मेष [चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ]
काम रुक-रुक कर होंगे। शत्रु पक्ष अचानक से आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकता है। अनावश्यक खर्चे नियन्त्रित रखें। आपको पड़ोसियों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिये।

तुला [रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते]
विदेश में शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। ऑनलाइन कारोबार में लाभ मिल सकता है। लोग आप पर पूर्ण विश्वास रखेंगे।

वृषभ [ई,उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो]
अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को किसी से शेयर न करें। रक्तचाप की समस्या होने की आशंका है। भोजन और बाकी दिनचर्या अनुशासित रखें। अनावश्यक विचारों से आपको बचना चाहिये।

वृश्चिक [तो,ना,नी, नू,या,यी,यू]
अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना लाभकारी होगा। बड़े भाई-बहनों को लेकर चिन्तित हो सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। महत्वपूर्ण अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं, लापरवाही से बचें।

मिथुन [क, की,कु,घ, ड,छ,के,को,ह]
अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इस समय सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं। जीवनसाथी आपके एक अच्छे मित्र की भूमिका निभायेगा। मन की बातें उनसे साझा कर सकते हैं।

धनु [ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ढ, भे]
कारोबार में सबकुछ आपके अनुसार ही होता प्रतीत होगा। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अत्यन्त आनन्दित रहने वाले हैं। मित्रों से लम्बी बातचीत हो सकती है।

कर्क [हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो]
यदि मन में किसी प्रकार का कोई भय था, तो वह दूर हो सकता है। धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। जीवनसाथी के प्रति मन में सम्मान और आदर का भाव उत्पन्न होगा।

मकर [भो, जा,जी, जू, खा, खू, गा, गी,]
जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नशीले पदार्थों का सेवन न करें। दाम्पत्य सम्बन्धों के लिये समय निकालें। आवश्यक निर्णय अचानक लेना पड़ेगा। यात्राओं के लिये सप्ताह सुखद नहीं रहेगा।

सिंह [मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टु, टे]
सन्तान को लेकर कुछ परेशानी होने की आशंका है। गृह निर्माण के कार्य तेजी से पूर्ण होंगे। प्रेम सम्बन्धी मामलों में निराशा हाथ लग सकती है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान प्राप्त हो सकता है।

कुंभ [गू, गे, गो,सा, सी, सू, से, सो, दा]
शुभ समाचार मिल सकते हैं। रिटेल से जुड़े लोगों को उत्तम धन-लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धैर्यपूर्वक किये गये कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार की जरूरतों पर धन खर्च करना पड़ेगा।

कन्या [टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो]
नया कार्य आरम्भ करना उचित नहीं है। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। निजी रिश्तों को लेकर गम्भीर रहें।

मीन [दी, दू, थे, झ, ञ, दे, दो, चा, चि]
नये घर या जमीन में निवेश सकते हैं। जीवनसाथी से सलाह लेना आपके लिये हितकर होगा। दूसरों की बातों को अधिक तूल न दें।

आचार्य राजेश शास्त्री, जयपुर

शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा सहित अन्य नए स्थलों पर किया जाए फोकस

राजस्थान को वर्ष पर्यन्त वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए-दीया कुमारी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान को अब केवल 6 महीने नहीं, बल्कि वर्ष पर्यन्त वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के साथ-साथ शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और पुष्कर जैसे पर्यटन स्थलों को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में एक्सप्लोर किया जाए। दिया कुमारी रविवार को जयपुर के कूकस स्थित एक होटल में आयोजित इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहले से ही विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन राजस्थान की ब्रांड पहचान को और विस्तार देने के लिए अन्य पर्यटन स्थलों को भी इस मानचित्र पर लाना आवश्यक है। शेखावाटी की हवेलियां, जैसलमेर का रेगिस्तान, बांसवाड़ा-डूंगरपुर की प्राकृतिक सुंदरता, भरतपुर का वन्यजीव और पुष्कर की धार्मिक आभा - ये सभी स्थल वेडिंग टूरिज्म के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वेडिंग टूरिज्म को वर्षभर बढ़ावा मिलने से स्थानीय कारीगरों, होटल, ट्रांसपोर्ट और इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

"अन्य स्थलों को भी पर्यटन के नक्शे पर लाना जरूरी"

दिया कुमारी ने एक होटल में आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय विवाह एवं पर्यटन सम्मेलन' को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान को अब केवल 6 महीने नहीं, बल्कि पूरे वर्ष विवाह के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. डिप्टी सीएम ने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर विवाह समारोहों के आयोजन के लिए पहले से ही विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन राजस्थान की पहचान को और विस्तार देने के लिए अन्य पर्यटन स्थलों को भी विवाह पर्यटन के मानचित्र पर लाना जरूरी है।

दिया कुमारी बोलीं- इससे रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

उन्होंने कहा कि इसे सालभर बढ़ावा मिलने से स्थानीय कारीगरों, होटल कारोबार, परिवहन और कार्यर्क म आयोजन (इवेंट मैनेजमेंट) उद्योग से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. आईडब्ल्यूटीसी के निदेशक अरशद हुसैन ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य भारत और दुनिया के पर्यटन बोर्ड, होटल उद्योग, विवाह समारोह आयोजकों और कार्यक्रम प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे कारोबार के नए अवसरों और वैश्विक साझेदारी पर चर्चा कर सकें. आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश ने भी कार्यर्क म को संबोधित करते हुए कहा, "आंध्र प्रदेश पर्यटन को आईडब्ल्यूटीसी का आधिकारिक भागीदार बनने पर गर्व है। हमारा उद्देश्य राज्य के समुद्री तटों, आध्यात्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर को विवाह आयोजनों एवं पर्यटन के वैश्विक उद्योग से जोड़ना है। इस तरह के मंच राज्यों के बीच सहयोग और पर्यटन विकास के नए अवसर पैदा करते हैं।"

इंटर-डिस्कॉम स्थानांतरण नीति

निर्णय में देरी, पारदर्शिता पर सवाल और कर्मचारियों की बढ़ती प्रतीक्षा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित इंटर-डिस्कॉम स्थानांतरण नीति अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हजारों बिजली कर्मचारियों के पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। सरकार द्वारा इस दिशा में पहल, समिति का गठन तथा बैठक आयोजित किए जाने के बावजूद आज तक कोई स्पष्ट समय-सीमा, आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट अथवा नीति का प्रारूप सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्न उठ रहे हैं।

सबसे अधिक प्रभावित कर्मचारी

राजस्थान के अनेक बिजली कर्मचारी वर्षों से अपने गृह डिस्कॉम से दूर सेवाएँ दे रहे हैं। इससे उनके पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, आर्थिक स्थिति तथा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि एक पारदर्शी और समान अवसर वाली स्थानांतरण नीति लागू होती है, तो इससे कर्मचारियों के मनोबल के साथ-साथ विभागीय कार्यकुशलता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव

समिति की पहली बैठक हो चुकी है, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष, सुझाव अथवा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? किसी भी जनहित और कर्मचारी हित से जुड़े विषय में पारदर्शिता लोकतांत्रिक प्रशासन की मूल अपेक्षा होती है। जानकारी के अभाव में कर्मचारियों के बीच असमंजस और अनिश्चितता बढ़ रही है।

क्या प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी हो रही है?

जब समस्या वर्षों से चिन्हित है और उसके समाधान के लिए समिति भी गठित की जा चुकी है, तब यह अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित समय के भीतर नीति का मसौदा तैयार कर निर्णय लिया जाए। यदि प्रर्कि या अपेक्षा से अधिक समय ले रही है, तो उसके कारणों को सार्वजनिक करना भी उतना ही आवश्यक है। इससे भ्रम और अनावश्यक अटकलों पर विराम लगेगा। यदि सरकार सिद्धांततः इस नीति के पक्ष में है, तो फिर निर्णय प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है? क्या कोई प्रशासनिक, कानूनी, वित्तीय अथवा तकनीकी बाधा है? यदि है, तो उसका स्पष्ट विवरण कर्मचारियों और आमजन के सामने रखा जाना चाहिए। पारदर्शी संवाद से विश्वास मजबूत होता है, जबकि जानकारी का अभाव अविश्वास को जन्म देता है।

सरकार और विभाग से अपेक्षित कदम

- समिति की पहली बैठक के मुख्य बिंदु और प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
- नीति निर्माण की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए।
- यदि कोई प्रशासनिक या कानूनी बाधा है, तो उसका आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जाए।
- इंटर-डिस्कॉम स्थानांतरण नीति लागू करने की निश्चित समय-सीमा घोषित की जाए।
- निर्णय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जानकारी समय-समय पर सार्वजनिक की जाए।

तुलाई कांटों पर रवन्ना जारी करने की पुरानी व्यवस्था निष्प्रभावी होगी

खनन क्षेत्र में 1428 तुलाई कांटें लाइव ऑटोमाइज्ड, 45462 खनिज परिवहन वाहनों पर वीटीएस

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राज्य में 1428 खनिज तुलाई कांटों को ऑटोमाइज्ड कर लाइव कर दिया गया हैं वहीं खनिज परिवहन में इस्तेमाल हो रहे 45462 वाहनों को व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। इससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रकिया के सरलीकरण के साथ ही खनन क्षेत्र में राजस्व छीजत पर भी कारगर रोक लग सकेगी। खानलीजधारक आगे आकर तुलाई कांटों के ऑटोमाइजेशन और वीटीएस व्यवस्था से जुड़े। तुलाई कांटों पर रवन्ना जारी करने की पुरानी व्यवस्था जल्द ही निष्प्रभावी हो जाएगी और नई व्यवस्था के तहत ही रवन्ना जारी हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खनिज क्षेत्र में जीरो टॉलरेस की नीति अपनाने के साथ ही खनन क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने पर जोर देते रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों व मार्गदर्शन में खनिज क्षेत्र में पारदर्शी और सरलीकृत व्यवस्था के तहत तुलाई कांटों का ऑटोमाइजेशन और व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था लीजधारकों और विभाग दोनों के लिए ही लाभकारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में माइनिंग सेक्टर में राज्य के खानधारकों और राज्य सरकार दोनों के ही व्यापक हितों को देखते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है और समयबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वयन व प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने बताया कि विभाग द्वारा खनन तुलाई में कार्यरत 1764 तुलाई कांटों में हार्डवेयर इंस्टाल कर 1428 तुलाई कांटों को लाइव कर दिया गया हैं। साफ्टवेयर इंस्टाल 336 तुलाई कांटों को एक दो दिन में लाइव कर दिया जाएगा। शेष रहे 461 तुलाई कांटों को भी इस माह के अंत तक साफ्टवेयर इंस्टाल कर लाइव कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तुलाई कांटों पर वजन में हेराफेरी, एक ही वाहन को नंबर प्लेट बदलकर या छिपा कर तुलाई कर ई-रवन्ना जारी करने और इसी तरह अन्य कारणों को गंभीरता से लेते हुए तुलाई कांटों का ऑटोमाइजेशन और खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया।

एसीएस अपर्णा अरोरा ने बताया कि विभाग द्वारा आरआईएफडी की नई व्यवस्था के तहत खनिज परिवहन में लगे वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय करते हुए 45462 वाहनों को वीटीएस व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ओसतन 20 हजार रवन्ना प्रतिदिन जारी होने लगे हैं।

श्री वार्ष्णेय वैश्य स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर की नई कार्यकारिणी सर्वसम्मति से गठित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। वार्ष्णेय वैश्य समाज की प्रतिष्ठित संस्था श्री वार्ष्णेय वैश्य स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर की द्विवर्षीय कार्यकारिणी (2026-2028) का चुनाव श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर, गोविन्द देव जी मंदिर परिसर, सिटी पैलेस (चांदनी चौक) के निकट, मुख्य चुनाव अधिकारी संजय वार्ष्णेय (धावास) के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया के उपरांत नीरज कुमार वार्ष्णेय (मुरलीपुरा को अध्यक्ष, ई. विक्रम गुप्ता (वैशाली नगर) को महासचिव तथा श्री कांता प्रसाद गुप्ता (मुरलीपुरा) को कोषाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। भगवान श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी के समक्ष नव-निर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज की सेवा, संगठन की गरिमा एवं विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की शपथ ग्रहण की। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुकेश गुप्ता, पूर्व महासचिव संजय कुमार वार्ष्णेय (पी.डब्ल्यू.डी.) तथा पूर्व कोषाध्यक्ष गिरीश गुप्ता के कार्यकाल में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डॉ. विनोद गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता, कालीचरण गुप्ता, विजय गुप्ता, विनय अग्रवाल (वार्ष्णेय), कमल गुप्ता, मुकुल वार्ष्णेय, आदर्श गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, विष्णु अग्रवाल (वार्ष्णेय), प्रभात गुप्ता, संजय गुप्ता तथा अजय गुप्ता (खिरणी फाटक) सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं सदस्य उपस्थित रहे। चुनाव के साथ ही श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी भजन संध्या का भी आयोजन किया गया।

सहस्रघट का किया आयोजन

जयपुर @ जागरूक जनता। सहस्रघट का आयोजन आज तक के सबसे सुंदर और शानदार आयोजन और लजीज प्रसादी के साथ सभी ने बड़े उमंग और उत्साह भाग लेकर सहयोग किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार तथा आचार्य शास्त्री जी और उनकी टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने शानदार झांकी और विद्वान पंडितो द्वारा मंत्रोचरण और भजनों द्वारा सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। कार्यक्रम में इंद्रदेव को प्रसन्न कर बारिश भी कार्रवाई तथा नए सदस्यों का भी बहुत-बहुत स्वागत और सभी आने वाले सदस्यों और समिति के अभी तक वंचित सदस्यों से आग्रह है कि यह सभी वन सदस्यता ग्रहण कर सेक्टर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें।

---

31 अगस्त तक चलेंगे फॉलो-अप शिविर, 22 विभाग रहेंगे सक्रिय

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक कार्ययोजना क्रियान्वित की गई है। सफलता से संपन्न हुए ग्रामीण सेवा शिविर-2026 (12 जून से 15 जुलाई) के क्रम में अब प्रदेशभर में 21 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक फॉलो-अप शिविर आयोजित किए जाएंगे।

22 विभागों की रहेगी सहभागिता

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व टी. रविकांत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, फॉलो-अप शिविरों में राजस्व विभाग सहित पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित शासन के 22 प्रमुख विभाग प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

जनहित में नियमों का सरलीकरण

भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक अब जिला अथवा तहसील मुख्यालय के स्थान पर संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी। भूमि आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने की उद्घोषणा अवधि को भी 15 दिवस से घटाकर 7 दिवस कर दिया गया है, जिससे प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव हो सकेगा। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स तथा संबंधित 22 विभागों के अधिकारी शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।

ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के दौरान हस्तांतरित शक्तियां फॉलोअप शिविर में भी रहेंगी जारी

आबादी विस्तार हेतु आरक्षित राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन किये जाने के लिए राज्य सरकार को अधिरोपित शक्तियां जिला कलक्टर को हस्तांतरित की गई हैं। आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि आरक्षित किये जाने के लिए जिला कलक्टर को अधिरोपित शक्तियां शिविर प्रभारी को हस्तांतरित की गई हैं। अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने के संबंध में, राजस्व अभिलेख / खातों का शुद्धिकरण, सार्वजनिक / राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन /आरक्षण की उपखण्ड अधिकारी को अधिरोपित शक्तियां शिविर प्रभारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा) को हस्तांतरित की गई हैं।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने गोद लिए सांगानेर थाने का किया निरीक्षण

अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और जनसेवा को बनाएं और प्रभावी-शर्मा

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने गोद लिए सांगानेर पुलिस थाने का सोमवार को निरीक्षण किया। उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों की अनुपालना एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने थाना परिसर, रिकॉर्ड संधारण, अपराध अनुसंधान, लंबित प्रकरणों के निस्तारण, जनसुनवाई व्यवस्था तथा पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को उत्कृष्ट थाना की अवधारणा के अनुरूप कार्यों को और गति देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त जयपुर श्री सचिन मित्तल, उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कुंवर राष्ट्रदीप, पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजीता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री पारस जैन एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री हरिशंकर शर्मा उपस्थित रहे। पुलिस महानिदेशक श्री शर्मा ने थाना परिसर का निरीक्षण करने के बाद अनुसंधान अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि थाना पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होता है। यहां की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्धता का समावेश होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

ये निर्देश भी दिए

पुलिस महानिदेशक ने केस ऑफिसर योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने, महिला अत्याचार से संबंधित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में अनुसंधान पूर्ण कर प्राथमिकता से निस्तारण करने तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर समाप्त करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कमजोर वर्ग से जुड़े अपराधों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने, पुलिस सत्यापन समयबद्ध रूप से पूर्ण करने और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सामुदायिक पुलिसिंग को बनाए प्रभावी

शर्मा ने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। बीट अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर बैठकें कर आमजन को नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव तथा पुलिस की विभिन्न जनहितकारी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने, अनुशासन बनाए रखने तथा आमजन के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार को पुलिसिंग का मूल आधार बताया।

विधानसभा अध्यक्ष ने किया बालिका सैनिक स्कूल का शिलान्यास

अब अजमेर भी सैनिक स्कूलों के नक्शे पर, देशभर में नई पहचान बनेगी-देवनानी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। अजमेर के हिस्से में एक बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। अब अजमेर भी देश के उन चुनिंदा शहरों के नक्शे में शामिल होगा, जहां बालिका सैनिक स्कूल है। इस स्कूल में पहले साल में 200 बालिकाओं को प्रवेश मिलेगा। स्कूल में बालिकाओं को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को हाथीखेड़ा गांव बालिका सैनिक स्कूल की नींव रखी। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य बजट में अजमेर में बालिका सैनिक स्कूल की घोषणा कर प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए जा रहे पांच बालिका सैनिक स्कूलों में से एक अजमेर में बनाया जा रहा है। आज देश की महिलाएं सेना में हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और ऐसे में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल की स्थापना उन्हें राष्ट्रसेवा के लिए तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि परियोजना पूर्ण होने के बाद अजमेर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होगा, जहां बालिकाओं के लिए समर्पित सैनिक स्कूल संचालित होगा। हाथीखेड़ा स्थित विद्यालय परिसर के समीप वरुण सागर एवं अरावली पर्वतमाला का प्राकृतिक वातावरण इसे सैनिक प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए आदर्श स्थान बनाता है। बालिका सैनिक स्कूल प्रदेश की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय रक्षा सेवाओं एवं नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा तथा अजमेर को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा।

देवनानी ने कहा कि लगभग 20 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह विद्यालय अजमेर के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि होगा। नया परिसर 30 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा तथा इसका निर्माण समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के माध्यम से कराया जाएगा। निर्माण कार्य 15 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विद्यालय तक सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में ही लगभग 4.50 करोड़ रुपये की लागत से अप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रदेश की बेटियों को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं राष्ट्रसेवा की भावना से ओत-प्रोत करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस परिसर में 8.18 करोड़ रूपए से अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक-अत्याधुनिक क्लासरूम और लैब, सुसज्जित कक्षा-कक्ष, 5.18 करोड़ रूपए से 200 छात्राओं की क्षमता वाला आधुनिक हॉस्टल, 2 करोड़ रूपए की लागत से स्कूल स्टाफ के लिए कैंपस के भीतर आवासीय क्वार्टर, 1.50 करोड़ रूपए से इंडोर गेम्स हॉल, एक करोड़ रूपए की लागत से आउटडोर खेल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एवं टेनिस कोर्ट, परेड ग्राउंड, 45 लाख रूपए से बाउंड्री वॉल सहित आंतरिक सड़कें, पार्किंग, ट्यूबवेल सहित सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

बरलूट में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम में दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

सिरोही। राज्य सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत शनिवार को बरलूट स्थित राजकीय विद्यालय परिसर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी तथा जालौर-सिरोही सांसद लुम्बारामजी चौधरी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण का संकल्प है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी नियमित देखभाल भी करे, तभी यह अभियान सफल होगा।

सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया यह अभियान जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने युवाओं, विद्यार्थियों एवं आमजन से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का आह्वान किया। कांतिलाल पुरोहित ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। सभी को ऐसे जनहितकारी अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए।

कार्यक्रम में लगाए गए पौधे लब्धी सेवा संस्था के संरक्षण में उपलब्ध कराए गए। संस्था की ओर से मनीषा देओल के समन्वय एवं संरक्षण में पौधों की व्यवस्था की गई, जबकि पौधों का सहयोग एवं भामाशाह के रूप में योगदान पुखराज पी शाह द्वारा प्रदान किया गया। अतिथियों ने इस जनसहयोग की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी पहल बताया।

कार्यक्रम में खेताराम लोहार, अमराराम प्रजापत, सरपंच भारत माली, चुन्नीलाल माली, बसन्त भारती, मोहन सुआरा, स्थानीय विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। सभी ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

अंत में संस्था प्रधान संतोष आर्य ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया तथा पर्यावरण संरक्षण के इस जनअभियान को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प दिलाया। राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने सर्किट हाउस में आमजन की परिवेदनाएं सुनी।इस दौरान उन्हें विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाएं प्राप्त हुई जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को निस्तारण करने व परिवादी को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

देलवाडा मार्ग पर भालुओं की चहलकदमी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

माउंट आबू। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भालुओं का दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई हैरानी भी नहीं होती कि यह भालू हमें दिन में दिखाई दे रहे हैं या फिर शाम को या फिर दोपहर को भी माउंट आबू वासियों के लिए तैयार आम बात हो चली है। रविवार की शाम को जब देलवाड़ा रोड से अचानक जा रहे थे तो एक साथ चार मोटे तगड़े भालू दिखाई दे जो सन सरोवर मार्ग के निकट से आ रहे थे और पास की ही जंगल में चारों एक-एक कर उतरकर अपने-अपने रास्ते पर चले गए गनीमत यह रही कि उसे समय सड़क से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था वरना शायद अनहोनी का खतरा हो जाता।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि आपको कहीं भी कोई वन्य जीव विकास वन्य प्राणी सांप, अजगर या कोई विषैला जीव दिखाई दे तो आप उसे वैसे ही दूरी बना ले उसके ना तो पास जाने की कोशिश करें नहीं उसे छेड़ने का प्रयास करें अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है इसी तरह से भालू या लेपर्ड भी जब दिखाई दे तो आप उसे निश्चित दूरी बनाकर रखें ।जब वह अपने आप अपने रास्ते पर चले जाए तो फिर आप वहां से निकाल सकते हैं अन्यथा इसके लिए वन विभाग की भी मदद ले सकते हैं

12 प्रतिशत तक महंगा हुआ टोल, जयपुर-दिल्ली और खाटूश्यामजी का सफर हुआ महंगा

नई दिल्ली @ जागरूक जनता। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जयपुर से कनेक्ट होने वाले कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर टोल दरों में संशोधन कर दिया है, जो बीती मध्य रात्रि 12 बजे से प्रभावी रूप से लागू हो चुकी हैं। इस नई दर सूची के लागू होने के बाद कार, जीप, टैक्सी, मिनी बस और बड़े व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क में 8 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर से दिल्ली के एकतरफा सफर के लिए कार चालकों को अब पहले मिलने वाले 375 रुपये के बजाय 395 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, यानी एक तरफ की यात्रा पर सीधे 20 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया है। यह बढ़ोतरी न केवल दैनिक यात्रियों और व्यापारियों बल्कि वीकेंड पर दिल्ली या खाटूश्यामजी दर्शन के लिए निकलने वाले आम परिवारों के बजट को प्रभावित करेगी।

जागरूक जनता jagrukjanta.net फेसबुक पेज
पढ़े, जुड़े और आगे बढ़े
हर खबर से आपको रखें
अपडेट जागरूक जनता
www.facebook.com/jagrukjantanews

माधव यूनिवर्सिटी में एनसीसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों के सफल आयोजन पर 4 राज बटालियन एनसीसी ने जताया आभार

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

आबूरोड। माधव यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित 4 राज बटालियन एनसीसी, सिरोही के दो वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों के सफल आयोजन में विश्वविद्यालय प्रशासन एवं स्टाफ के उत्कृष्ट सहयोग के लिए एनसीसी ने आभार व्यक्त किया है।

4 राज बटालियन एनसीसी, सिरोही के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल नरपत सिंह ने 17 जुलाई 2026 को जारी प्रशंसा पत्र में विश्वविद्यालय के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि शिविरों के सफल संचालन में माधव यूनिवर्सिटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने बताया कि एटीसी-1 शिविर 21 से 30 जून तक आयोजित हुआ, जिसमें 535 कैडेट्स एवं 40 स्टाफ ने भाग लिया, जबकि एटीसी-2 शिविर 1 से 10 जुलाई तक आयोजित किया गया, जिसमें 602 कैडेट्स एवं 40 स्टाफ शामिल रहे।

प्रशंसा पत्र में उल्लेख किया गया कि दोनों शिविरों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास, भोजन, प्रशिक्षण मैदान, ऑडिटोरियम एवं कक्षा-कक्षों की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल एवं सुव्यवस्थित बनाने में अहम योगदान दिया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्टाफ ने हर आवश्यकता पर तत्परता से सहयोग प्रदान किया। पानी एवं विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी विश्वविद्यालय के सहयोगी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेफ्टिनेंट कर्नल नरपत सिंह ने 4 राज बटालियन एनसीसी, सिरोही के समस्त कैडेट्स एवं एनसीसी स्टाफ की ओर से माधव यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉ. राजकुमार, चेयरपर्सन हिम्मत सिंह देवल, प्रो-प्रेसिडेंट डॉ. सुशील भार्गव, रजिस्ट्रार डॉ. भावेश कुमावत, होम्योपैथिक विभाग की निदेशक डॉ. भारती देसाई तथा विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि माधव यूनिवर्सिटी लंबे समय से एनसीसी की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती रही है। ऐसे प्रशिक्षण शिविर युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और राष्ट्रसेवा के संस्कार विकसित करने के साथ-साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं।

कनिष्ठ विधि अधिकारी (जयपुर विकास प्राधिकरण) प्रतियोगी परीक्षा-2025

26 एवं 27 जुलाई को जयपुर में होगा परीक्षा का आयोजन, कल अपलोड किए जाएंगे प्रवेश-पत्र

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी (जयपुर विकास प्राधिकरण) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 26 एवं 27 जुलाई 2026 को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2.30 से सांय 5.30 बजे तक जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा।

परीक्षांतर्गत प्रत्येक प्रश्नपत्र में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र 23 जुलाई 2026 को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवें। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं।

गुरु पूर्णिमाः ज्ञान, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का महापर्व

यतेन्द्र पाण्डेय
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
@jagrukjanta.net

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। भारतीय संस्कृति में यदि किसी संबंध को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है तो वह गुरु और शिष्य का संबंध है। इसलिए कहा गया है-

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥"

आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों और जीवन-दर्शन का महापर्व है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य का वास्तविक उत्थान केवल धन, शक्ति या तकनीक से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान से होता है। गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास से माना जाता है, जिन्होंने वेदों का संहिताकरण किया, महाभारत तथा अठारह पुराणों की रचना की। इसी कारण यह दिवस व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। भारत की ऋषि परंपरा में गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का शिल्पी माना गया है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान को हर हाथ तक पहुँचा दिया है, तब भी गुरु की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई है। सूचना (Information) और ज्ञान (Knowledge) में अंतर होता है। सूचना मशीन दे सकती है, लेकिन विवेक, मूल्य, चरित्र और जीवन का उद्देश्य केवल गुरु ही सिखा सकता है। AI उत्तर दे सकता है, पर सही निर्णय लेने की क्षमता और नैतिक दृष्टि गुरु ही विकसित करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा को केवल रोजगार तक सीमित न रखकर चरित्र निर्माण, भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य-आधारित शिक्षा पर बल देती है। यह गुरु की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। दुर्भाग्य से आज शिक्षा का बढ़ता व्यवसायीकरण, परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था और नैतिक मूल्यों का क्षरण गुरु-शिष्य संबंध की आत्मीयता को चुनौती दे रहा है। ऐसे समय में गुरु पूर्णिमा केवल औपचारिक सम्मान का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का पर्व भी है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने शिक्षकों, माता-पिता, मार्गदर्शकों और जीवन में प्रकाश देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं? भारतीय परंपरा में माता-पिता प्रथम गुरु, शिक्षक द्वितीय गुरु और जीवन का अनुभव तृतीय गुरु माना गया है। समाज, प्रकृति, पुस्तकें और परिस्थितियाँ भी हमें निरंतर शिक्षा देती रहती हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का संदेश केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था–"शिक्षा वह है जो मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करे।" ऐसी शिक्षा तभी संभव है जब गुरु स्वयं आदर्श, अनुशासन, करुणा और सत्यनिष्ठा का प्रतीक हो। वहीं शिष्य में भी विनम्रता, जिज्ञासा और सीखने की ललक होना आवश्यक है। आज भारत विश्वगुरु बनने की बात करता है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक शक्ति या तकनीकी विकास से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ऐसे गुरु चाहिए जो ज्ञान के साथ संस्कार दें और ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो सफलता के साथ संवेदनशीलता भी सीखें। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश यही है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह मनुष्य को बेहतर इंसान, जिम्मेदार नागरिक और राष्ट्रनिर्माता बनाए। यदि हम अपने जीवन में किसी एक गुरु के बताए मार्ग पर भी ईमानदारी से चल सकें, तो यही इस पावन पर्व की सबसे बड़ी साधना होगी। "गुरु वह दीप है जो स्वयं जलकर दूसरों का जीवन प्रकाशित करता है। गुरु पूर्णिमा उस दीप के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और संकल्प का पावन उत्सव है।"

- अखिल भारतीय शहीद सुशील कुमार शर्मा फाउंडेशन

पुलिस प्रशासन की निगेहबानी पर प्रश्नचिह्न !

देव भूमि में असुरों की एन्जॉय पार्टी!

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

माउंट आबू। अब अवश्य आइए क्योकि यह तो आबू राज बन चुका। ओर ऐसे में जब आबू राज में सरे राह टूरिस्ट्स पॉइंट्स पर देवो के मध्य असुर सुरापान से एन्जॉय करते हुए नजर आ जाएं तो जाहिर यहां के राज काज पर प्रश्नचिन्ह लगना लाजिमी है। सो तस्वीरों को देखकर आप भी बताइए इसीलिए हमने माउंट आबू का नाम आबूराज किया था ,राज के सुशासन की तस्वीरें कुछ इस तरह नजर आएं, खुलेआम हो रही शराब पार्टी व जगह जगह लोग जाम छलखाते ज़्यादा दिखाई देने लगे। शायद मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल सही सही बोल गए थे, अब आबू में बहुत ही जल्द बड़ा होने वाला है, सो हो भी रहा है, ओर सरे आम सड़को पर जगह जगह दिखाई भी दे रहा है। और कोई अजरज नही हैरानी नही कि, आपको माउंट आबू जो कि अब आबू राज है उसमें शराब व शराबियों का राज आ चुका है। आपको जब चाहिए जितने बजे चाहिए शराब हर समय उपलब्ध होगी।

जी हाँ, आबूराज में रात्रि को आठ बजे के बाद भी पूरी रात व सुबह दस से पहले भी मिल जाएगी । बस दाम चुकाइये, ओर जम कर के जाम लीजिए कोई रोक टोक नही । क्यो कि यहां शराब की दुकाने मात्र दिखावे के लिए ही बन्द रहती है। बैक डोर व साइड पर सफ्लाय के साथ कुछ दुकाने तो सरेआम बेडधक रात्रि आठ बजे बाद भी खुली रहती है।

इसलिए एसएचओ साहब की मनमर्जी व भजनलाल सरकार की नीतियों व उनके द्वारा कहे गए कथनों को आप भी ध्यान सुनिए कि कैसे व किस कदर उनके जाने के बाद यहां के अफसर उनकी कथनी को पलीता लगाने का कार्य कर रहे है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह देवताओं की तपोभूमि है। उनके जाने के बाद भजनलाल सरकार के अफसरों ने ही अपनी वाहवाही करवाकर इस आबूराज मे क्या क्या सरे राह करने की छूट यहां आने वाले सैलानियों को दे दी है उसकी बानगी आप भी देखिए ओर बताइए कि, यहां शासन व प्रशासन व खुद को दबंग कहलावाकर गौरवान्वित होने वाले शहर के स्टेशन हेडक्वाटर्स ऑफिसर्स SHO किस गफलत में सुबह शाम ट्रेक सूट पहनकर आगे पीछे दो दो पुलिस जवान लेकर इन सब को होता हुआ देख कर भी अनजान बने हुए है या उनकी सरपरस्ती में ही यह सब खुलेआम हो रहा है।

अब जरा गुरू शिखर के दत्तात्रेय मन्दिर के निकट की तस्वीरें देख लीजिए, आपका मन ललचाएगा, एक पैक तो आपका भी बनता है । और मौसम जिसकी मार्केटिंग आजकल वे स्वयं अपने फोटो शूट्स से कर रहे है उससे तो यह सब होना कोई हैरानी नही दर्शाता , एक आम व्यक्ति के मन मे हैरानी व हताशा पैदा करता है कि शासन जहां आम दुकानदारों से गन्दगी के नाम पर किराए के नाम वसूली अभियान में व्यस्त है,तो पुलिस अफसर ओर जिसके जिम्मे ही यहां की शान्ति व्यवस्था का दारोमदार है । वह अपना कर्तव्य किस तरह निर्वहन कर रहा है । ऐसी तस्वीर देखकर भी आपको शासन व प्रशासन के प्रति संवेदना नजर आए तो हमें बताइए की कितना संवेदनशील है हमारा प्रशासन ?

मुकुंदरा टाइगर रिजर्वः सफारी तैयारी, लेकिन सड़क नहीं, मार्ग सबसे बड़ा रोड़ा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

कोटा। राजस्थान के बहुप्रतीक्षित मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में अक्टूबर महीने से जंगल सफारी शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग ने सफारी संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। नोलाव स्थित मुख्य प्रवेश द्वार लगभग तैयार है, जहां केवल रंग-रोगन और कुछ अंतिम औपचारिक कार्य शेष है। करीब 30 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक भी विकसित किया जा चुका है। इसके बावजूद जंगल सफारी की शुरुआत से पहले सबसे बड़ी चुनौती गागरोन से नोलाव मेन गेट तक पहुंचने वाली सड़क बनी हुई है, जो अब तक नहीं बन सकी है।

कच्चा और उबड़-खाबड़ रास्ता

विडंबना यह है कि जिस मार्ग से होकर पर्यटकों को सफारी स्थल तक पहुंचना है, वहां आज भी कच्चा और उबड़-खाबड़ रास्ता है। बारिश के मौसम में यह मार्ग कीचड़ और गड्ढों से भर जाता है, जिससे आवागमन बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में अक्टूबर से प्रस्तावित जंगल सफारी की सफलता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

सड़क मंजूरी मिली, लेकिन प्रक्रिया अटकी

गागरोन से नोलाव तक सड़क निर्माण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक क्लीयरेंस पहले ही मिल चुकी है, और बजट स्वीकृत कर दिया गया है। इसके बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग अब तक न तो टेंडर प्रक्रिया शुरू करवा सका और न ही निर्माण कार्य। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। हालांकि, वर्तमान समय में भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए, तब भी सड़क पूरी होने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है। ऐसे में अक्टूबर में प्रस्तावित जंगल सफारी सड़क बनने से पहले ही शुरू होने की संभावना है।

सिर्फ पर्यटक ही नहीं, ग्रामीण भी प्रभावित

यह मार्ग केवल जंगल सफारी तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि नोलाव, लक्ष्मीपुरा, नारायणपुरा, राजपुरा और गोलाभाव सहित कई गांवों के लोगों के आने-जाने का मुख्य मार्ग भी है। बारिश के दिनों में सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, बच्चों के स्कूल जाने और कृषि कार्यों के लिए आने-जाने में भी मुश्किलें होती हैं। ग्रामीण लंबे समय से इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सड़क बन जाती है, तो न केवल उनकी समस्याएं दूर होंगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

पर्यटन को मिलेगी नई पहचान

विशेषज्ञों का मानना है कि मुकुंदरा में जंगल सफारी शुरू होने से झालावाड़ पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान बना सकता है। इससे होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन इन संभावनाओं को साकार करने के लिए सबसे पहले सुरक्षित और सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अब सभी की निगाहें सरकार पर है कि क्या अक्टूबर से पहले सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर पर्यटकों और ग्रामीणों को कच्चे रास्ते के सहारे ही मुकुंदरा की जंगल सफारी तक पहुंचना पड़ेगा।

ग्रामीणों में खुशी और चिंता दोनों

जंगल सफारी शुरू होने की खबर से स्थानीय लोगों में उत्साह है। उनका मानना है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के खुलने से झालावाड़ पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा, और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही ग्रामीण यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पर्यटक मुख्य गेट तक ही आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, तो सफारी का संचालन कितना सफल हो सकेगा।

सबसे महत्वपूर्ण नोलाव क्षेत्र

वन विभाग के अनुसार, नोलाव क्षेत्र मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 30 किलोमीटर का सफारी ट्रैक तैयार किया गया है। पिछले साल में सबसे अधिक समय तक बाघों की मौजूदगी इसी क्षेत्र में दर्ज की गई थी। यही कारण है कि नोलाव को जंगल सफारी के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में झालावाड़ जिले में टाइगर रिजर्व का यही एकमात्र प्रवेश द्वार प्रस्तावित है।

प्रदेश का 'मिनी स्विट्ज़रलैंड' बना प्रदूषण का 'हॉटस्पॉट'

रिसर्च में खुलासा- 20 गुना से भी अधिक पॉल्यूशन

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

अजमेर। पहली नजर में किसी बर्फीली जगह सा लगने वाला यह नजारा पर्यटकों को काफी लुभाता है. इसे राजस्थान का 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है. अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर से महज 3-4 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह असल में मार्बल डंपिंग यार्ड है, जो यहां आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है. लेकिन यही टूरिस्ट प्लेस अब प्रदूषण का हॉटस्पॉट भी बन चुका है. राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की रिसर्च में सामने आया है कि इस पर्यटन स्थल का प्रदूषण स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की निर्धारित सीमा से 4 से 12 गुना है. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अनुशंसित सीमा से 20 से 50 गुना अधिक प्रदूषण पाया गया।

एशिया का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है ये जगह

यह एशिया का सबसे बड़ा मार्बल डंपिंग यार्ड है. यहां सालों से मार्बल कटाई के दौरान निकलने वाला अवशेष और पाउडर जमा किया जाता रहा है. करीब 350 एकड़ में फैले इस स्थान पर 700 से अधिक टैंकर द्वारा लगभग 22 लाख लीटर मार्बल स्लरी डाली जाती है. इसके चलते धीरे-धीरे यह कचरा पहाड़ों का रूप ले चुका है. केंद्रीय विश्वविद्यालय की रिचस्च ने पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि यह पहला अध्ययन है, जिसमें डंपिंग यार्ड के 15 किलोमीटर के दायरे में सिंचित और वर्षा आधारित कृषि भूमि, भूजल और वायु गुणवत्ता का आंकलन किया गया. इसके साथ ही 'परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी' तकनीक से प्रदूषकों की सांद्रता और एक्स-रे विवर्तन विश्लेषण के माध्यम से प्रदूषण के खनिजीय स्वरूप को स्टडी किया गया. एएएस तकनीक के जरिए मिट्टी और पानी में मौजूद धातुओं और अन्य प्रदूषकों की मात्रा का पता लगाया जाता है।

यह अनोखी लोकेशन विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है.

यह जगह सिर्फ एक डंपिंग साइट नहीं, बल्कि फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है. यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने कैमरे में इस अनोखे नजारे को कैद करना चाहता है. बर्फ जैसे सफेद और आकर्षक स्वरूप के कारण यह स्थान 'प्री-वेडिंग फोटोशूट', व्यावसायिक शूटिंग और पर्यटन के लिए बेहद लोकप्रिय हो गया है. यहां प्रतिदिन करीब 5 हजार पर्यटक आते हैं. जबकि वीकेंड और छुट्टियों में यह संख्या 20 हजार तक पहुंच जाती है।

53 फीसदी क्षेत्रवासियों को सांस लेने में दिक्कत

सबसे अधिक प्रदूषण उस समय दर्ज किया गया, जब औद्योगिक गतिविधियां चरम पर थीं और तेज सतही हवाएं चल रही थीं. रिसर्च में सामने आया कि मार्बल की धूल से लगातार पर्यावरण को नुकसान और स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। प्रोफेसर शर्मा ने कहा, "स्वास्थ्य पर इसका असर भी स्पष्ट दिखाई देता है. सर्वेक्षण में 53 फीसदी स्थानीय निवासियों और 70 प्रतिशत मार्बल उद्योग के श्रमिकों ने सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की. जबकि 56 से 84 प्रतिशत लोगों ने गले से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया।" पीएचडी शोधार्थी बसंत बिजारणिया ने बताया कि अध्ययन के दौरान आसपास की मिट्टी और भूजल में भारी धातुएं पाई गईं. रिसर्च में रेगलुर मॉनिटरिंग, प्रभावी नियामक नियंत्रण और जनस्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप के दखल की सलाह दी गई।

एमबीए- एग्रीबिजनेस 2026 बैच के विद्यार्थियों का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित

जो संस्थान जीवन में आगे बढ़ाएं, उसके लिए शुक्रगुजार रहे-जैतावत

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय की ओर से एमबीए- एग्रीबिजनेस 2026 बैच के विद्यार्थियों का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मारवाड़ी कैटलिस्ट के संस्थापक एवं निदेशक सुशील शर्मा रहे। समारोह में विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कुलगुरु प्रोफेसर जैतावत ने कहा कि विदाई विद्यार्थियों के लिए नई मंजिलों की ओर उड़ान भरने का मौका होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जो संस्थान आपको जीवन में आगे बढ़ने के लायक बनायें उसके प्रति सदैव शक्रगुजार होना चाहिए।

छोटी स्तर से शुरुआत कर बढ़े आगे

कार्यक्रम के दौरान अतिथि सुशील शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि जिसके जैसा बनना चाहो, सर्वप्रथम उसका सपना देखो, इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। छोटी स्तर से शुरुआत कर स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतरीन पोजीशन पर पहुंचे हुए लोगों की कहानी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इनोवेशन सिर्फ़ सिलिकॉन वैली तक ही सीमित नहीं है। उनके लिए, असली संभावनाएँ छोटे शहरों और वहाँ के उद्यमियों में छिपी हैं। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी कैटलिस्ट्स के ज़रिए, उनका मकसद स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना हैं। उन्होंने कहा चाहे नौकरी करें या व्यवसाय, दोनों में शत प्रतिशत मेहनत करें, साथ ही अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग व सेलिंग पर भी पूरी पकड़ होनी चाहिए।

विद्यार्थी इनोवेशन पर काम करें

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद निदेशक, शिक्षा डॉ सुरेंद्र कुमार मूड ने कहा कि इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, बाजार की मांग को देखते हुए विद्यार्थी नए आइडिया व इनोवेशन पर लगातार काम करें। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन देते हुए प्रबंधन संकाय की विशेषाधिकारी डॉ नलिनी रामावत ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए निरंतर मेहनत व अपने लक्ष्य पर टिके होने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान प्लेसमेंट पाने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। समारोह में धन्यवाद ज्ञापन डॉ प्रशांत साहनी ने किया, मंच संचालन डॉ माया शर्मा ने किया।

ऑपरेशन के दौरान पेट में 'मोप' छोड़ने का आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

चित्तौड़गढ़। शहर के प्रतापनगर निवासी लोकेश चौधरी ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर दक्ष हॉस्पिटल, कुंभानगर के चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ पर उनकी पत्नी के सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शिकायत में संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के अनुसार, उनकी पत्नी जया चौधरी को गर्भावस्था के दौरान 2 मई 2026 को दक्ष हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल सिजेरियन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 6 मई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लोकेश का आरोप है कि कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। पहले चित्तौड़गढ़ में उपचार कराया गया, लेकिन राहत नहीं मिलने पर 24 जून को अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि पूर्व में हुए ऑपरेशन के समय पेट में मेडिकल उपयोग का कपड़ा (मोप) छूट गया था, जिससे शरीर में गंभीर संक्रमण फैल गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संक्रमण के कारण लीवर और तिल्ली प्रभावित हुए तथा बड़ी आंत फटने से पुनः बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान पेट से मोप निकालने का भी दावा किया गया है। परिवादी ने बताया कि उपचार पर अब तक करीब 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। साथ ही, उनकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है और नवजात शिशु भी मां के दूध से वंचित हो गया है। परिवादी ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में दक्ष हॉस्पिटल के चिकित्सकों एवं संबंधित मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 50, 117(3), 118, 125 एवं 200 के तहत मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

पीपराली की नीरमा ने NEET 2026 में रचा इतिहास

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

गुड़ामालानी/पीपराली। जिला बालोतरा के पीपराली गांव की बेटी नीरमा मेघवाल ने NEET 2026 परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है। नीरमा ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 14,071वीं तथा SC वर्ग में 313वीं रैंक हासिल की।

नीरमा ने कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा नैनिहाल गांव राणोदर, चितलवाना में रहकर पूरी की। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता स्व. हनुमानाराम का निधन हो गया था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद नीरमा ने निरंतर मेहनत और परिवार के सहयोग से यह शानदार मुकाम हासिल किया। मामा वीरधाराम बरवड़, पशुधन निरीक्षक, के सकारात्मक सहयोग एवं मोटिवेशन से नीरमा को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों एवं क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला जारी है। नीरमा की सफलता पर पूर्व सरपंच खुमाराम बेरड ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर मेहनत और परिवार के सहयोग से नीरमा ने NEET जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है।

बिरला शिक्षा केंद्र, चित्तौड़गढ़ में गरिमामय ढंग से आयोजित हुआ इन्वेस्टिचर सेरेमनी समारोह

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

चित्तौड़गढ़। बिरला शिक्षा केंद्र, चित्तौड़गढ़ में नवगठित विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण एवं अलंकरण के लिए इन्वेस्टिचर सेरेमनी का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिरला सीमेंट फैक्ट्री एजुकेशन सोसायटी के चेयरमैन जयंत कांडपाल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात नव-निर्वाचित विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों को सम्मानपूर्वक बैज एवं सैश पहनाकर उनके दायित्व सौंपे गए। विद्यालय के स्कूल छात्र कप्तान के रूप में कर्णम डछोरा तथा छात्रा कप्तान के रूप में शांभवी चारस्वत ने पदभार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि जयंत कांडपाल ने परिषद के पदाधिकारियों को निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों को नेतृत्व, अनुशासन, सेवा भावना एवं जिम्मेदारी का महत्व बताते हुए कहा कि विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और चरित्र का सशक्त निर्माण होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। बिरला सीमेंट फैक्ट्री एजुकेशन सोसायटी के सचिव हेमंत किशोर श्रीवास्तव ने नव-निर्वाचित विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

31 अगस्त तक आयोजित होगा 'फॉलो अप शहरी सेवा शिविर-2026'

बालोतरा @ जागरूक जनता। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर विकास न्यास, बालोतरा द्वारा 21 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक 'फॉलो अप शहरी सेवा शिविर-2026' का आयोजन किया जाएगा। नगर विकास न्यास के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि शिविर के दौरान सीसी एवं डामर सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क, सफाई एवं सौंदर्यीकरण, नालियों की मरम्मत व रखरखाव, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव तथा जनसुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आवासीय कॉलोनियों से संबंधित पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नाम हस्तांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति सहित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण भी किया जाएगा। शिविर में लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने, 31 दिसंबर 2021 से पूर्व बसी कॉलोनियों के 90-ए संबंधी प्रकरणों तथा ले-आउट अनुमोदन सहित राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी किए जाएंगे।

घर मंगवाये जागरूक जनता

सदस्यता फार्म दिनांक ....

जागरूक जनता हिन्दी अखबार एक उद्देश्य, एक मिशन, एक विश्वास के साथ आमजन की समस्याएं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक गलियारा, भौगोलिक दृष्टिकोण को एक-दूसरे से साझा करने के लिए एक सेतु का काम कर रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं तकनीकी जानकारी पहुंचाकर शहरी एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। जागरूक जनता समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों के साथ- अपने पाठकों के बीच उपस्थित रहता है।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 250/- ☐ दो वर्ष रु. 450/- ☐ तीन वर्ष रु. 600/- ☐ पांच वर्ष रु. 1000/-

डाक से नियमित रुप से निम्न पते पर जागरूक जनता भेजने के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर जागरूक जनता के नाम भेज रहा हूं। फोन-पे, पेटीएम-9829329070

नाम / संस्था का नाम ....

पता : ....

....

फोन .... पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

राशि (रुपए) .... बैंक का नाम ....

डिमान्ड ड्राफ्ट / मनीऑर्डर क्रमांक ☐☐☐☐☐☐ (डीडी/एमओ जागरूक जनता के नाम भेजें)

• सदस्यता रजिस्ट्रेशन क्रं. ....रसीद क्रं. ....

दिनांक .... हस्ताक्षर

सदस्यता हेतु लिखे प्रसार प्रभारी →

जागरूक जनता सकारात्मक हिन्दी अखबार

बी-132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.) मो.- 9829329070, 9928022718

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक ज्ञानेन्द्र मिश्रा के लिए जैमन प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी-1-68, रोड नम्बर-14, वीकेआई, जयपुर से मुद्रित एवं प्रशासनिक और विज्ञापन कार्यालय : बी-132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर-302039 से प्रकाशित। फोन : 0141-3587886

वह विश्वविद्यालय, जहाँ आपके बच्चों की सफलता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है

बीस वर्ष पहले, ऐमिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना दिल्ली-एनसीआर की पहली गैर-लाभकारी नॉट-फॉर-प्रॉफिट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी और यह देश की शुरुआती प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में से एक है। विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने और ऐसा माहौल तैयार करने के उद्देश्य से, जो विद्यार्थियों को सफल, आत्मविश्वासी, भावनात्मक रूप से संतुलित और उच्च नैतिक मूल्यों वाले नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित करे, हमने भारत और दुनिया भर के शिक्षा, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया।

विद्यार्थियों की व्यक्तिगत देखभाल की हमारी मजबूत संस्कृति, शोध और नई सोच पर आधारित शैक्षणिक वातावरण, उत्कृष्ट शिक्षकों और वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन, मूल्यों और अनुशासन से युक्त शिक्षण प्रणाली, मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियाँ, उद्योग जगत से मजबूत जुड़ाव जिसके परिणामस्वरूप बेहतर प्लेसमेंट मिलते हैं, हमारे वैश्विक कैंपस का नेटवर्क तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं ने ऐमिटी यूनिवर्सिटी को लगातार दिल्ली-एनसीआर की सर्वोच्च रैंक प्राप्त निजी यूनिवर्सिटी, देश की अग्रणी यूनिवर्सिटियों में से एक तथा विश्व की शीर्ष 3% यूनिवर्सिटियों में स्थान दिलाया है।

यदि आप अपने बच्चों को दिल्ली-एनसीआर में पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनमें ऐमिटी अन्य सभी नॉट-फॉर-प्रॉफिट प्राइवेट विश्वविद्यालयों से एक कदम आगे है:

शोध आधारित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित शिक्षकों के साथ

- सबसे उच्च स्कोपस एच-इंडेक्स (212) - यह ऐमिटी के शिक्षकों और वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे उच्च स्तरीय शोध कार्य की गुणवत्ता को दर्शाता है
- विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में सर्वाधिक (84) फैकल्टी सदस्य - यह सूची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित की जाती है
- सबसे अधिक पेटेंट (500+) प्राप्त - जिनमें से अनेक का सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण भी किया गया है
- सबसे अधिक रामालिंगास्वामी एवं रामानुजन फेलो (45) - ये भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त वे प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक हैं, जो विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से भारत लौटकर शोध कार्य कर रहे हैं
- सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं (500+) की सर्वाधिक संख्या
- फैकल्टी द्वारा विकसित 5,300+ केस स्टडीज़ - जिन्हें दुनिया भर के 3,000 से अधिक संस्थानों ने खरीदा है, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, केपीएमजीऔर मैकेंज़ी एंड कंपनी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं
- 2,500 से अधिक शोधार्थियों के साथ सबसे बड़ा Ph.D. एवं फेलोशिप कार्यक्रम
- कैंपस में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटिंग सुविधा (10 पेटाफ्लॉप)
- भारत सरकार से नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवॉर्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय

प्रतिभाशाली विद्यार्थी, व्यक्तिगत देखभाल की संस्कृति और भविष्य-केंद्रित पाठ्यक्रम

- छात्रों द्वारा 1,450 से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए हैं तथा 9,500 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित किए गए हैं
- विद्यार्थियों को खुराना, मैरी क्यूरी, भारती एयरटेल जैसी स्कॉलरशिप / फेलोशिप तथा GATE फाउंडेशन, DST और ICMR जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से रिसर्च सहायता मिलती है
- ऐमिटी इन्क्यूबेटर ने 100 से अधिक छात्र-स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक स्थापित करने में मदद की है तथा इन स्टार्टअप्स के लिए ₹350 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया है
- प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति के लिए पर्सनल मेंटर्स और 24×7 काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध है, साथ ही अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति अटेंडेंस पर विशेष जोर दिया जाता है
- मेधावी विद्यार्थियों को ₹220 करोड़ से अधिक मूल्य की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल करने वाले अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक
- ऐमिटी बाउंडलेस एक फ्लेक्सिबल अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें विद्यार्थी अपने करियर लक्ष्यों के अनुसार 90 विषयों में से माइनर, सेकंड मेजर और ओपन इलेक्टिव्स चुन सकते हैं।

वैश्विक मान्यताएँ और प्रतिष्ठित रैंकिंग्स

- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग में निजी विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थानों में शामिल
- अमेरिका की WASC (स्टैनफोर्ड, USC, UC जैसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली) और ब्रिटेन की QAA से मान्यता प्राप्त एकमात्र विश्वविद्यालय, जो ऐमिटी की वैश्विक गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है
- ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रैंकिंग एजेंसियों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स और Times Higher Education (UK) द्वारा विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त
- India Today द्वारा 11 वर्षों से भारत की टॉप निजी विश्वविद्यालयों में शामिल
- Times Higher Education (UK) रैंकिंग्स 2026 में इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त
- Times Higher Education (UK) सब्जेक्ट रैंकिंग्स में कंप्यूटर साइंस तथा बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स विषयों के लिए भारत की नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय के रूप में रैंक प्राप्त

अंतरराष्ट्रीय अवसरों के माध्यम से वैश्विक अनुभव

- 5,000 से अधिक विद्यार्थी Study Abroad Program के तहत ऐमिटी और उसके पार्टनर कैंपसों में लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, दुबई, पेरिस, मेलबर्न तथा अन्य प्रमुख शहरों में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त करते हैं
- Dual Degree Program के तहत विद्यार्थियों को ऐमिटी यूनिवर्सिटी के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया की पार्टनर यूनिवर्सिटी से दूसरी डिग्री मिलती है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और बेहतर करियर अवसर प्राप्त होते हैं।

उत्कृष्ट प्लेसमेंट और उच्च शिक्षा के अवसर

- Times Higher Education (UK) द्वारा लगातार चौथे वर्ष ऐमिटी को उन चुनिंदा वैश्विक विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है, जो सबसे अधिक रोज़गार-योग्य ग्रेजुएट तैयार करते हैं
- ऐमिटी के छात्र दुनिया की अग्रणी कंपनियों में कार्यरत हैं, जैसे मैकेंजी एंड कंपनी, डेलॉइट, केपीएमजी, गूगल, यूनिलीवर, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएँ
- विद्यार्थियों का चयन विश्व की अग्रणी विश्वविद्यालयों में हुआ है, जैसे हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, कैम्ब्रिज, जॉन्स हॉपकिन्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, येल...
- ऐमिटी के कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर विद्यार्थियों को करियर के लिए पूरी तरह तैयार करने में सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत प्लेसमेंट सपोर्ट, इंटर्नशिप, उद्योग जगत के CEOs के साथ संवाद, लाइव प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यू और करियर मार्गदर्शन जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

ऐमिटी स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और पीएच.डी. स्तर पर 400 से अधिक डिग्री प्रोग्राम प्रदान करता है, जिनमें करियर-केंद्रित विषयों और क्षेत्रों में पढ़ाई करने का व्यापक विकल्प उपलब्ध है।

- Acting
- Actuarial Science
- Advertising
- Aeronautical Engg.
- Aerospace Engg.
- Agriculture
- Animation
- Anthropology
- Applied Science
- Architecture
- Artificial Intelligence
- Automobile Engg.
- Avionics
- Banking & Insurance
- Biochemistry
- Hospital Administration & Public Health
- Hotel Management
- Information Technology
- Interior Design
- International Relations
- Journalism
- Law
- Life Sciences
- Logistics & Supply Chain Management
- Management
- Marine Science
- Mass Communication
- Mathematics
- Bioinformatics
- Biotechnology
- Business Economics
- Chemistry
- Clinical Psychology
- Cognitive Science
- Commerce
- Computer Applications
- Computer Sc. Engg.
- Construction & Real Estate Mgmt.
- Cyber Security
- Data Science
- Defence & Strategic Studies
- Defence Technology
- Digital Marketing
- Economics
- Education
- Electric Vehicle Tech.
- Engineering
- English Literature
- Entrepreneurship
- Environmental Sc.
- Fashion
- Film, TV & Web Series
- Finance
- Fine Arts
- Food Technology
- Foreign Language
- Forensic Science
- Forestry & Wildlife Sc.
- Genome Engineering
- Geography
- Geo Informatics System & Remote Sensing
- Horticulture
- Microbial Science
- Molecular Medicine & Stem Cell Research and Cancer Biology
- Nanomedicine
- Nanotechnology
- Natural Resources & Sustainable Development
- Neuropsychology & Neurosciences
- Nuclear Sc. & Tech.
- Nutrition & Dietetics
- Occupational Therapy
- Performing Arts
- Pharmacy
- Physical Education
- Physics
- Physiology
- Physiotherapy
- Political Science
- PR & Event Mgmt.
- Product Design
- Psychology
- Public Policy
- Quantum Technologies
- Sanskrit Studies
- Social Work
- Sociology
- Space Science
- Special Education
- Statistics
- Travel & Tourism
- Urban Planning/ Design
- Virology & Immunology
- Visual Effects & Animation
- Zoology

and many more...

स्कॉलरशिप्स	100%	50%
200+ स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु स्कॉलरशिप्स:		
कक्षा 12 (agg.)*	95%	90%
190+ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु स्कॉलरशिप्स:		
कक्षा 12 (agg.)*	95%	90%
स्नातक (agg.)	80%	75%

ये स्कॉलरशिप्स छात्रों की पूरी शैक्षणिक फीस को कवर करती हैं, सिर्फ उसका एक हिस्सा नहीं।

अधिक जानकारी हेतु देखें: ***amity.edu/scholarships***

*CBSE / ISC Boards

आवेदन करने के लिए **www.amity.edu** पर जाएँ।

- ऐमिटी यूनिवर्सिटी, सेक्टर-125, नोएडा : www.amity.edu/noida | हेल्पलाइन : 0120-2445252
- ऐमिटी यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम कैंपस : www.amity.edu/gurugram | हेल्पलाइन : 7303-399-399

AMITY UNIVERSITY

संपादक : **ज्ञानेन्द्र मिश्रा** मो.-9829329070, फोन : 0141-3587886, ईमेल : **jagrukjantanews@gmail.com** (सभी मामलों का न्याय क्षेत्र जयपुर) * पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के जिम्मेदार। **संपादकीय कार्यालय** : 132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर (राजस्थान)-302039 समाचार संपादक- **चेतेन्द्र कुमार मिश्रा**

दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे राजस्थानी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के पात्र परिवार अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। पिछले 6 महीनों में 30 हजार से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया। योजना से जुड़े देशभर के करीब 30 हजार अस्पतालों में मुफ्त उपचार उपलब्ध है।

राजस्थान के पात्र परिवारों को अब इलाज के लिए राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख रुपये तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज मिल रहा है। राज्य सरकार की आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू होने के बाद पिछले छह महीनों में 30 हजार से ज्यादा लोगों ने दूसरे राज्यों के अस्पतालों में बिना इलाज का खर्च उठाए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया है। इससे गंभीर बीमारियों के मरीजों को बड़ी राहत मिली है।

राज्य से बाहर भी मिलेगा कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को हर साल 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। योजना में 2,179 तरह के उपचार शामिल हैं। इनमें सामान्य बीमारियों के साथ कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, डायलिसिस और अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है।

15 दिसंबर 2025 से लागू हुई नई व्यवस्था

पहले कई मरीजों को बेहतर इलाज के लिए गुजरात, दिल्ली या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन वहां इलाज का खर्च और दूसरी परेशानियां सामने आती थीं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2025 से आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की। अब पात्र परिवार दूसरे राज्यों में पीएमजेएवाई से जुड़े अस्पतालों में भी बिना पैसे दिए इलाज करा सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है।

हजारों मरीजों को मिला बड़ा फायदा

अब तक इस व्यवस्था के तहत 5,959 क्लेम किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 17 करोड़ रुपये से अधिक है। इन क्लेम्स के जरिए मरीजों ने हार्ट स्टेंट, हार्ट बायपास सर्जरी, कैंसर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, जनरल सर्जरी और सिजेरियन डिलीवरी जैसे कई महंगे इलाज मुफ्त में कराए हैं। सबसे ज्यादा मरीजों ने गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में उपचार कराया है।

देशभर के हजारों अस्पतालों में सुविधा

इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देशभर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े करीब 30 हजार अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इनमें 16 हजार से अधिक सरकारी और 14 हजार से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पताल इस नेटवर्क का हिस्सा हैं।

सरकार का उद्देश्य हर मरीज तक बेहतर इलाज पहुंचाना

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान का हर पात्र नागरिक जरूरत पड़ने पर राज्य से बाहर भी बिना किसी आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज करा सके। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था इसी सोच के साथ शुरू की गई है, ताकि गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक चिंता न करनी पड़े।

पेटा इंडिया वी पशु चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम

55 अश्वों को लगायी गयी दर्द रहित लगाम

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

माउंट आबू। माउंट आबू स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में पीईटीए इंडिया और पशुपालन विभाग, माउंट आबू-व-आबू रोड के संयुक्त तत्वावधान में घोड़ों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 55 अश्वों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें दर्द रहित लगाम लगाई गईं। शिविर में क्षेत्र के घोड़ा पालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों ने घोड़ों की शारीरिक जांच की, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया और आवश्यक चिकित्सीय मार्गदर्शन प्रदान किया। शिविर प्रभारी डॉ. संजय तावड़े और नोडल अधिकारी डॉ. शैलेश प्रजापति ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य घोड़ों के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, समय पर रोगों की पहचान करना और

पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने घोड़ा पालकों के उत्कृष्ट सहयोग की सराहना की। सिरोही से आए अश्व विशेषज्ञ डॉ. आवेश खान ने भी बताया कि 55 अश्वों को इस शिविर से लाभ मिला। विभाग ने पीईटीए इंडिया से आए महेश त्यागी और चुमकी के विशेष सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। पशुपालन विभाग ने भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी और पशु कल्याण संबंधी शिविरों का आयोजन जारी रखने की बात कही, ताकि पशुपालकों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलता रहे।

"ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे" के तहत बाल विवाह, साइबर अपराध व नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान

छात्रों ने जीवन भर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

माउंट आबू। PM केंद्रीय विद्यालय, आबू पर्वत में "ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे" पर बाल विवाह, साइबर अपराध व नशे पर जागरूकता अभियान; छात्रों ने जीवन भर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा तालुका विधिक सेवा समिति, आबू पर्वत के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर (आर.जे.एस.) के गरिमामयी सान्निध्य में आज पीएम केंद्रीय विद्यालय, आबू पर्वत में "ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे" अभियान के अंतर्गत एक समेकित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए अध्यक्ष श्याम सुंदर ने विद्यार्थियों से स्नेहपूर्ण और प्रेरणादायक संवाद स्थापित किया। उन्होंने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा ही व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति की आधारशिला है। अध्यक्ष ने बच्चों को अपने भविष्य के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करने और शिक्षा के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया।

वर्तमान डिजिटल युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष ने साइबर अपराधों के प्रकार–ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, साइबर बुलिंग इत्यादि–और उनसे बचाव के व्यावहारिक उपायों के बारे में सरल, व्यवहारिक जानकारी दी। उन्होंने तकनीक के सुरक्षित, जिम्मेदार और सकारात्मक उपयोग का सन्देश देते हुए विद्यार्थियों को सतर्क रहने की सीख दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण "Say No to Drugs, Say Yes to Your Dreams; Drugs Are Not Cool: Protect Your Mind, Body and Future" विषयक प्रेरक संदेश रहा। अध्यक्ष ने साफ कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और भविष्य को नष्ट कर देता है, जबकि शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक सोच सफलता के मार्ग खोलते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, अपने सपनों को साकार करने और राष्ट निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

सरासर नाकामी या दिखावटी मुक़ाम

नक्की लेक बाजार में शराबी हुड़दंग ने पुलिस की चौकसी पर प्रश्नचिन्ह

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

माउंट आबू। नक्की लेक के मुख्य बाजार में बीती रात शराब के नशे में एक युवक ने खुलेआम उत्पात मचाया; घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने उसकी आपत्तीजनक हरकतें मोबाइल पर रिकॉर्ड कीं और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जबकि पुलिस की समय पर मौजूदगी और रोकथाम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई और सवाल

स्थानीय थाने की त्वरित गिरफ्तारी के दावों के बावजूद यह मामला पहले से चल रही शिकायतों का नया उदाहरण है कि निर्धारित समय के बाद शराब की बिक्री और सार्वजनिक जगहों पर शराबखोरी पर नियंत्रण सुविधाजनक नहीं रहा है पहले भी निर्धारित समय के बाद शराब विक्रय और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने की रिपोर्टें दिखाई जा चुकी हैं; इन रिपोर्टों का प्रशासन और पुलिस की नीतियों पर सीमित असर दिखा है, जो इस तरह की घटनाओं के बढ़ने का कारण माना जा रहा है ।

घटना का दृश्य और प्रतिक्रिया

युवक ने बाजार में कपड़े उतारने सहित आक्रामक व्यवहार किया; भीड़ के बीच यह तमाशा कुछ देर तक चलता रहा और कई लोगों ने वीडियो बनाकर उसे साझा किया जा रहा है । उपस्थित लोगों का कहना है कि पुलिस देर से पहुंची, मौके पर जब तक रि या-प्रतिरि या हुई, तब तक घटना का वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर फैल चुका था, जिससे कानून-व्यवस्था की छवि को धक्का लगा है।

सामुदायिक भरोसा और असर

स्थानीय लोगों में पुलिस पर भरोसा झलकने के बजाय घबराहट और असंतोष दिखा; कई नागरिक पूछ रहे हैं कि "अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास" जैसे नारों का वास्तविक असर आम जनता तक पहुँच रहा है या नहीं पारंपरिक हिल-स्टेशन की शांति और सुरक्षा के प्रति यह घटना नकारात्मक संदेश दे रही है, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन (कल्याण कोष) की प्रथम राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक संपन्न

हमारा एक ही संकल्प, अग्र समाज में सहयोग की हो भावना-मित्तल

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन (कल्याण कोष) की प्रथम राष्ट्रीय ऑनलाइन

जूम बैठक बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार मित्तल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुशीला फरमानिया ने किया। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े कुल 18 राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने सहभागिता करते हुए संगठन की भावी योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया। बैठक के प्रारंभ में राष्ट्रीय चेयरमैन श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने संगठन की स्थापना के उद्देश्य, भावी कार्ययोजना, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा कल्याण कोष की कार्यप्रणाली पर विस्तृत एवं प्रेरक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक पदाधिकारी नियमित जनसंपर्क एवं सेवा-भाव से कार्य करे, तो कल्याण कोष समाज के आर्थिक रूप से कमजोर अग्र बंधुओं के लिए एक सशक्त सहारा बन सकता है।

बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन (कल्याण कोष) गाइड लाइन-2026 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया गया। राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय समन्वय समिति की भूमिका, संगठनात्मक उत्तरदायित्व तथा कार्य-प्रणाली पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों को संस्था द्वारा संचालित अग्र शिक्षा योजना, अग्र स्वास्थ्य योजना, अग्र लाडली विवाह योजना, वृद्ध कल्याण योजना एवं आपदा कल्याण योजना की जानकारी दी गई। साथ ही आय संग्रहण हेतु फॉर्म-12 तथा सहायता आवेदन हेतु फॉर्म-13 के उपयोग एवं महत्व से भी अवगत कराया गया। बैठक का प्रमुख आकर्षण संस्था की महत्वाकांक्षी "जन सहयोग कूपन योजना-2026" रही। जानकारी दी गई कि "प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, एक रुपये के समतुल्य वार्षिक 365 रुपए सहयोग" के माध्यम से समाज के अधिकाधिक परिवारों को इस सेवा अभियान से जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में 500 पुस्तिकाएँ (5,000 कूपन) मुद्रित कर अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके साथ ही "पंच पदक सहयोग प्रोत्साहन योजना" एवं "चार पदक कूपन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट सहयोग कर्ताओं एवं सक्रिय पदाधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों के पदक एवं सम्मान प्रदान किए जाएंगे।

बैठक में "सहायता राशि आबंटन प्रक्रिया विनियमन" के प्रमुख प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए सहायता वितरण में पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व एवं एकरूपता सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया गया। अध्यक्ष की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, यह भी स्वीकृत किया गया कि 51,000/- सहयोग श्रेणी में प्रायोगिक रूप से, दिवंगत माता अथवा पिता की स्मृति में "सिल्वर स्मृति पदक" प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय का सभी सदस्यों ने स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार मित्तल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल धन संग्रह करना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग एवं विश्वास की स्थायी व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल्याण कोष में प्राप्त कुल सहयोग राशि का 70 प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लाडली विवाह योजनाओं पर, 15 प्रतिशत वृद्ध एवं आपदा कल्याण योजनाओं पर तथा केवल 15 प्रतिशत प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्ययों पर व्यय किया जाएगा।

कल्याण कोष के अधीन चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों विशेषतः "जन सहयोग कूपन योजना-2026" के कुशल संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने अपील की, कि अधिकाधिक अग्र बंधु इस सेवा अभियान से जुड़ें एवं इसे सफल बनाएं।

बैठक के अंत में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुशीला फरमानिया ने सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के सफल समापन की घोषणा की गई।

सांवलिया सेठ में रिकॉर्ड 38 करोड़ का चढ़ावा, दानपात्र में मिली 20 से अधिक देशों की करेंसी और 103 किलो चांदी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

चितौड़गढ़। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार के मासिक दानपात्र की गिनती पूरी हो गई. इस बार रिकॉर्ड 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार 862 रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ. दानपात्र से 29.77 करोड़ रुपये करोड़ रुपये प्राप्त हुए. भक्तों ने दानराशि के अलावा स्वर्ण व रजत भी खासा चढ़ाया गया. करीब 1 किलो 138 ग्राम सोना, 103 किलो 497 ग्राम चांदी और 20 से अधिक देशों की विदेशी मुद्रा भी चढ़ावे में मिली।

गिनती में जुटे रहे 150 से अधिक कार्मिक

मंदिर में 150 से अधिक कार्मिक दानराशि की गिनती में लगे रहे और 7 दिनों से दानराशि की गिनती की. मंडफिया स्थित 5 बैंकों के कार्मिक भी मौजूद रहे. 13 जुलाई को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मन्दिर मण्डल के प्रशासनिक अधिकारी और मन्दिर मण्डल अध्यक्ष व सदस्यों की मौजूदगी में मासिक भण्डार खोला गया. मंगलवार (21 जुलाई) को अंतिम दौर सातवें चरण की गिनती हुई.

सांवरिया सेठ मंदिर में चढ़ावे की गिनती 7 चरणों में हुई.

वही भेंटकक्ष, ऑनलाइन व मनीऑर्डर से 8 करोड़ 45 लाख 96 हजार 2 रुपए का चढ़ावा मिला हैं. पहले चरण में 10 करोड़ 11 लाख 83 हजार, दूसरे चरण में 6 करोड़ 49 लाख, तीसरे चरण में 7 करोड़ 63 लाख 30 हजार और चौथे चरण में 3 करोड़ एक लाख और पांचवें चरण में एक करोड़ 90 लाख रुपए, छठे चरण में 53 लाख 70 हजार 955 रुपए और अंतिम सातवें चरण में 8 लाख 33 हजार 905 रुपए खोले गए।